RNI NO. DELHIN/2015/61881

www.srojvarta.in

मूल्य : 10 रूपये

सरोज वार्ता

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका | वर्ष-12 | अंक- 08 | पृष्ठ- 44 | अगस्त 2026



मक्का समझौते के बाद भारत की

बहुआयामी रणनीति

इजराइल से खाड़ी और हिंद-प्रशांत तक मजबूत किया मोर्चा

REG NO.-463868



UNITED SOULS CARE

WELFARE FOUNDATION

'Serving Humanity with Unity'

Darpan ID: DL/2026/1007917 12A: AAECU0917DE20251 80G: AAECU0917DF20261

Contact No.: 9555253051 / 9899864010 / 9456004121

E-mail : unitedsoulscarewelfarefoundati@gmail.com

Address : RZA-3/73, Gali No.3A, Durga Park, Delhi-110045

BREAKING NEWS

www.srojvarta.in



RNI NO. DELHIN/2015/61881
राष्ट्रीय
सरोज वार्ता
हिन्दी मासिक पत्रिका
मूल्यः 10 रूपये
वर्ष-12 । अंक - 08 । अगस्त 2026
संरक्षक : रामकुमार सिंह
प्रधान संपादक : जगत किशोर सोलंकी
संपादक : अनुराग प्रताप
विधि सलाहकार : ललित पराशर
ग्राफिक डिजाइनर : सहदेव माहौर
मार्किटिंग मेनेजर : कृष्ण कुमार (उत्तर प्रदेश)

ब्यूरो प्रमुख
उत्तर प्रदेश : कृष्ण कुमार
राजस्थान : सौमेंद्र सिंह
दिल्ली : रिचा जोशी
छत्तीसगढ़ : विजय कुमार

संपादकीय, विज्ञापन एवं प्रसार कार्यालय
सरोज वार्ता, आर जेड ए 3/73 गली न. 3ए दुर्गा पार्क नई दिल्ली-110045

फोनं,: 09456004121, 09555253051, 9899864010

www.srojvarta.in
sarojvartanews@gmail.com
srojvartanews@gmail.com

क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तर प्रदेश)
नियर हनुमार मंदिर, अमापुर सिद्धपुर रोड़, सिद्धपुर जिला, कासगंज

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। सभी पद अवैतनिक हैं। विज्ञापन की सत्यता की जांच स्वयं कर लें। इसकी जिम्मेदारी उनकी है, एवं इसके प्रकाशक एवं संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। पत्रिका से संबंधित सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायलय के अधीन होगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अनुराग प्रताप द्वारा मैसर्स जवाद लीठोफराफर (M/s Jawaad Lithofrapher) 3622, दीनाबेग, लाल कुंआ, दिल्ली : 6 द्वारा मुद्रित व आर.जेड. ए : 3/73, गली नं. 3ए दुर्गा पार्क नई दिल्ली : 45 से प्रकाशित

संपादक : अनुराग प्रताप

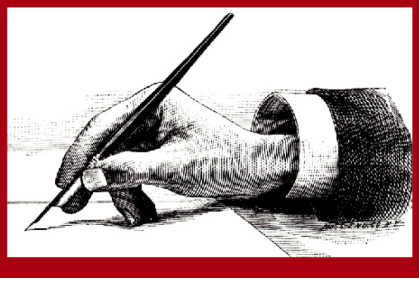
मेटा पर भारी जुर्माना

बच्चों पर सोशल मीडिया की स्वच्छंदता से पड़ने वाले घातक प्रभावों को लेकर भारतीय अभिभावक, शिक्षक व समाजविज्ञानी लंबे अरसे से गंभीर चिंता जताते रहे हैं। यह प्रभाव कितना भयावह व घातक है, ये बात पश्चिमी देशों की सरकारों, समाज व अदालतों को अब समझ में आई है। बच्चे समय से पहले परिपक्व हो रहे हैं। किशोरों की यौन हिंसा और वयस्कों जैसे अपराधों में संलिप्तता, इसके घातक प्रभावों की बानगी है। सोशल मीडिया पर बच्चों की नजर से ऐसे वीडियो गुजरते हैं, जिसमें स्वच्छंद यौन व्यवहार होता है। कुछ लोग व कंपनियां मुनाफे के लिए ऐसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति में पवित्र माने जाने वाले पारिवारिक रिश्तों, गुरु-शिष्य संबंधों और डॉक्टर मरीज के रिश्तों के वर्जित क्षेत्रों का अतिक्रमण करते नजर आते हैं। अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि कोरी स्लेट जैसे बालमन पर इसका कितना घातक असर पड़ता होगा? उसे पवित्र रिश्तों की दरकन और यौन-स्वच्छंद तथा गंभीर अपराध आम नजर आने लगते हैं। अमेरिका तथा कुछ अन्य विकसित देशों के स्कूलों में दना-दन गोलियां चलाते बच्चे इंटरनेट पर प्रसारित घातक सामग्री देखने से उपजी सनक की ही देन है। निस्संदेह, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु डिजिटल दुनिया को साफ-सुथरा रखने की जरूरत है। यही वजह है कि एक अमेरिकी अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मातृ संस्था मेटा पर 5,390 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना ज्यादा नहीं है क्योंकि पिछले साल कंपनी ने साठ अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। दरअसल, मेटा पर जुर्माना लगाने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अदालत ने कंपनी को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये अपने प्लेटफॉर्म में बदलाव करने को कहा है। दरअसल, न्यू मेक्सिको की अदालत ने स्वीकारा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिये घातक हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के कई राज्यों में सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं। फ्रांस व आस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर सक्रियता को लेकर बच्चों की उम्र की सीमा तय की गई है। हकीकत यह है कि कंपनी ने ये प्लेटफॉर्म अपने मुनाफे के लिये इस तरह तैयार किए हैं ताकि बच्चों को इसकी लत लग जाए। पिछले दिनों भारत सरकार ने मेटा के अधिकारियों को बुलाकर विरोध जताया था कि उसके एक प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापन भारी मुनाफा कमाकर प्रसारित किए गए। अमेरिकी अदालत ने भी माना है कि मेटा के प्लेटफॉर्म बच्चों को यौन शोषण से बचाने में विफल रहे हैं। यही वजह कि कोर्ट ने लगाए गए जुर्माने की राशि का एक भाग ऐसे पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। समय आ गया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को सामाजिक जवाबदेही के लिये बाध्य किया जाए। लेकिन यह नहीं हो कि अमेरिका के बच्चों के लिये अलग कानून और विकासशील व गरीब मुल्कों के बच्चों के लिये अलग कानून हो। हमारी सरकारों को भी इन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर गैर-कानूनी सामग्री प्रसारित करने के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना होगा।

● अनुराग प्रताप



जगत किशोर सोलंकी



सुरक्षा व पारदर्शिता जरूरी

ऐसे वक्त में जब नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने से उपजे छात्र आक्रोश से देश हाल ही में दो-चार हुआ है, देश के परीक्षा सिस्टम पर प्रतिभागियों का भरोसा कायम करना अपरिहार्य शर्त है। हाल के वर्षों में केंद्रीय स्तर और राज्यों में विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने, परीक्षाएं स्थगित होने और परीक्षा परिणामों को लेकर किंतु-परंतु होने की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। ऐसे में विश्वसनीयता के सवालों से जूझ रही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का इंटेलिजेंस, कानून लागू करने वाली एजेंसियों तथा डिफेंस फोर्सेज के अनुभवी लोगों को अपने परीक्षा सुरक्षा कमांड सेंटर में शामिल करने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। ये प्रयास दूसरी ओर हमें यह भी बताते हैं कि देश में महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं कितनी संवेदनशील व असुरक्षित हो गई हैं। नए प्रावधानों के अनुसार इसके टेस्ट सिक्योरिटी और लाइव ऑपरेशन्स अनुभाग के प्रस्तावित जनरल मैनेजर परीक्षा प्रक्रिया के लगभग हर संवेदनशील हिस्से की देखरेख करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्नपत्र तैयार करने, एन्क्रिप्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वितरण और रियल-टाइम मॉनिटरिंग भी शामिल रहेगा। विश्वास किया जाना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी निगरानी और परीक्षा के उपरांत डेटा एनालिसिस से परीक्षा व्यवस्था के पारदर्शी व विश्वसनीय होने की उम्मीद की जा सकती है। निस्संदेह, नीट प्रवेश परीक्षा विवाद के उपरांत प्रतिभागियों में भरोसा कायम करने की दिशा में यह एक गंभीर कोशिश होती नजर आती है। लेकिन एक बात तो तय है कि सिर्फ तकनीक के जरिए सिस्टम की खामियां दूर नहीं की जा सकतीं। हालिया नीट-यूजी पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई की जांच में एनटीए के अपने ही गोपनीय विभाग में खामियां पाई गई थीं, मसलन संतोषजनक ढंग से तलाशी न लेना, सीसीटीवी की अपर्याप्त निगरानी, जिम्मेदारियों का सही बंटवारा न होना तथा अंतिम प्रश्न सेट तक बहुत अधिक लोगों की पहुंच होना, जिसने परीक्षा प्रश्नपत्र के लीक संकट को जन्म दिया। दरअसल, सीबीआई जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि परीक्षा प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञ एक-दूसरे के संपर्क में थे, जिससे परीक्षा की गोपनीयता की सुरक्षा का एक बुनियादी नियम भंग हो गया। वास्तव में, नियमानुसार किसी भी एक व्यक्ति की पहुंच पेपर के सभी फाइनल सेट तक नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस कथित गड़बड़ी के लिए किसी हाई-लेवल हैकिंग की जरूरत नहीं पड़ने दी गई। दरअसल, भ्रष्ट लोगों ने परीक्षा प्रक्रिया की मामूली खामियों का फायदा चालाकी से उठाया। निस्संदेह, यह बात किसी भी साइबर खतरे के मुकाबले नीति बनाने वालों के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि दो सप्ताह पूर्व ही धर्मेंद्र प्रधान की जगह शिक्षा मंत्री बने प्रह्लाद जोशी के कंधों पर एक मजबूत, पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा सिस्टम बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए तुरंत विश्वास बहाली के लिए काम आरंभ करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल छात्र, बल्कि उनके अभिभावक व सारा देश फिर से निराश न हो सके। इसी तरह, एनटीए का प्रस्तावित कमांड सेंटर सिर्फ अफसरशाही का एक और विस्तार बनकर नहीं रह जाना चाहिए। वास्तविक अर्थों में इस प्रस्तावित कमांड सेंटर को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिले, स्पष्ट रूप से जवाबदेही तय हो और सुरक्षा में कोई गड़बड़ी पाए जाने पर परीक्षा प्रक्रिया को रोकने का अधिकार मिलना ही चाहिए। निश्चित रूप से देश के लाखों छात्रों के लिए परीक्षा व्यवस्था का निष्पक्ष व पारदर्शी होना ही पहली शर्त है। इसके बावजूद यदि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कड़ी परीक्षा से गुजरना अनिवार्य ही होगा, तो निस्संदेह, यदि एनटीए उसमें असफल रहता है, तो एजेंसी के भविष्य को लेकर कड़ा फैसला लिया जाना अपरिहार्य ही होगा। इसके अलावा, केंद्र के साथ ही राज्यों में भी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने वाली एजेंसियों के कामकाज व तौर-तरीकों पर नियमित निगरानी के लिए एक केंद्रीय ढांचा बनाया जाना चाहिए, जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा सिस्टम तैयार करना सुनिश्चित कर सके।



मक्का समझौते के बाद भारत की बहुआयामी रणनीति

इजराइल से खाड़ी और हिंद-प्रशांत तक मजबूत किया मोर्चा

सरोज वार्ता/ब्यूरो

भले ही तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान 7 अगस्त 2026 के मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के बाद इसे अपनी बड़ी रणनीतिक कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हों, लेकिन भारत ने इस बदलते शक्ति-संतुलन का जवाब किसी एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि कई दिशाओं में पहले ही तैयार कर लिया था। सिर्फ एक साल के ही घटनाक्रमों को देखें तो फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक पहुंचाया और रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, साइबर तथा अत्याधुनिक तकनीकों में सहयोग को नई धार दी। उसी फरवरी में फ्रांस के साथ रिश्तों को 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' तक पहुँचाया गया, जिसके तहत रक्षा उत्पादन, हैमर मिसाइलों के

> ● आंकड़ों के मुताबिक, तीनों देशों के पास संयुक्त रूप से करीब 14 लाख सक्रिय सैन्यकर्मी, 3,415 विमान, 6,046 टैंक, 344 नौसैनिक परिसंपत्तियां और लगभग 124.4 अरब डॉलर का वार्षिक रक्षा बजट है। सऊदी अरब पूंजी और रणनीतिक भूगोल देता है, तुर्की रक्षा उद्योग, ड्रोन, मिसाइल और नौसैनिक तकनीक देता है, जबकि पाकिस्तान मानवबल, सैन्य अनुभव और परमाणु क्षमता लेकर आता है।

भारत में संयुक्त निर्माण और उन्नत सैन्य तकनीक पर सहयोग बढ़ा है। इससे पहले अगस्त 2025 में फिलीपींस के साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी स्थापित की थी, जिसके केंद्र में रक्षा, समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत सहयोग है। साथ ही अप्रैल 2026 में दक्षिण कोरिया के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी को अगले पांच वर्षों के लिए नई रणनीतिक दिशा दी गई, जबकि मई 2026 में वियतनाम के साथ उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत रक्षा खरीद, समुद्री सुरक्षा, साइबर सहयोग और हिंद-प्रशांत में समन्वय को और मजबूत किया गया। मई 2026 में ही नीदरलैंड के साथ भी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। यानी पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी अरब ने जहां एक त्रिकोण बनाया है, वहीं भारत ने इजराइल, फ्रांस, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, नीदरलैंड और खाड़ी के महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े रणनीतिक रिश्तों का ऐसा व्यापक नेटवर्क खड़ा किया है, जिसमें रक्षा

तकनीक, मिसाइलें, समुद्री सुरक्षा, खुफिया सहयोग और रक्षा उत्पादन सभी शामिल हैं।

•भारत-इजराइल रक्षा सहयोग

हम आपको याद दिला दें कि ईरान युद्ध से ठीक पहले हुई प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा का सबसे बड़ा पहलू आधुनिक रक्षा तकनीक था। करीब 10 अरब डॉलर मूल्य के संभावित रक्षा सौदों में आयरन बीम जैसी लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली, आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो प्रणालियों की तकनीक, सटीक निर्देशित बम, लक्ष्य के ऊपर मंडराकर हमला करने वाले हथियार, नौसैनिक रक्षा प्रणालियां और अत्याधुनिक ड्रोन शामिल हैं। इससे साफ है कि भारत केवल हथियार खरीदने की दिशा में नहीं, बल्कि अपनी दीर्घकालिक सैन्य वास्तुकला को इजराइली तकनीक के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत-इजराइल सहयोग में 'भविष्य के जोखिमों की निगरानी' जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित व्यवस्था पर भी काम हो रहा है, जिसके जरिए भविष्य के सुरक्षा जोखिमों, सीमाई चुनौतियों और तकनीकी बदलावों का पहले से आकलन किया जा सकेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणना, अर्धचालक और साइबर सुरक्षा में संयुक्त शोध का अर्थ है कि भारत अपनी अगली पीढ़ी की सुरक्षा क्षमता केवल आज के युद्ध के लिए नहीं, बल्कि कल के युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखकर तैयार कर रहा है। साथ ही रक्षा उत्पादन में संयुक्त शोध, तकनीकी हस्तांतरण और घरेलू सह-उत्पादन 'आत्मनिर्भर भारत' को सैन्य शक्ति से जोड़ते हैं। इसी संदर्भ में इजराइल की प्रस्तावित 'गठबंधनों का षट्कोण' अवधारणा भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और अन्य साझेदारों के बीच सुरक्षा और आर्थिक सहयोग की परिकल्पना की गई है। इसका रणनीतिक संदेश यह है कि भारत पश्चिम एशिया और भूमध्यसागर में बन रहे नए शक्ति-संतुलन को केवल देख नहीं रहा, बल्कि अपने लिए वैकल्पिक रणनीतिक नेटवर्क भी तैयार कर रहा है।

•मक्का समझौते से जुड़े सवाल

अब आते हैं मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक प्रतिरोध का संकल्प लेते हुए कहा है कि तीनों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी पर हमला माना जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक, तीनों देशों के पास संयुक्त रूप से करीब 14 लाख सक्रिय सैन्यकर्मी, 3,415 विमान, 6,046 टैंक, 344 नौसैनिक परिसंपत्तियां और लगभग 124.4 अरब डॉलर का वार्षिक रक्षा बजट है। सऊदी अरब पूंजी और रणनीतिक भूगोल देता है, तुर्की रक्षा उद्योग, ड्रोन, मिसाइल और नौसैनिक तकनीक देता है, जबकि पाकिस्तान मानवबल, सैन्य अनुभव और परमाणु क्षमता लेकर आता है। लेकिन इस गठजोड़ को 'इस्लामिक नाटो' कह देना इसकी वास्तविक क्षमता का अंतिम प्रमाण नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमला होने की स्थिति में बाकी सदस्य वास्तव में कितनी और किस प्रकार की सैन्य सहायता देने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल अभी कोई स्थायी केंद्रीय संयुक्त सैन्य कमान स्थापित नहीं हुई है। यानी राजनीतिक घोषणा और वास्तविक संयुक्त युद्ध क्षमता के बीच अभी लंबी दूरी है।

•रणनीतिक साझेदारियों का नेटवर्क खड़ा कर रहा है हिंदुस्तान

साथ ही पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब के बीच बने नए रक्षा समीकरण को समझने के लिए केवल तीन देशों की सैन्य ताकत देखना काफी नहीं है। असली तस्वीर यह है कि पिछले एक साल में भारत ने भी अपनी रणनीतिक साझेदारियों और रक्षा सहयोग का दायरा तेजी से बढ़ाया है। अगस्त 2025 में भारत और फिलीपींस ने अपने संबंधों को औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी यानी रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। फरवरी 2026 में भारत-इजराइल संबंधों को शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी तक पहुँचाया गया। फरवरी में ही भारत और फ्रांस ने अपने रिश्तों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। मई 2026 में भारत और वियतनाम ने संबंधों को उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया। यूएई के साथ जनवरी 2026 में दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इन साझेदारियों की खासियत यह है कि ये केवल कागज पर कूटनीतिक घोषणाएं नहीं हैं। इनके पीछे रक्षा, समुद्री सुरक्षा, खुफिया सहयोग, तकनीक, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और रक्षा उत्पादन जैसे ठोस क्षेत्र जुड़े हैं। यानी पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी गठजोड़ अगर एक तरफ शक्ति का त्रिकोण बना रहा है, तो भारत दूसरी तरफ अलग-अलग क्षेत्रों में कई





मजबूत साझेदारों का नेटवर्क खड़ा कर रहा है।

• भारत-फिलीपींस रक्षा संबंध

सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण फिलीपींस है। भारत पहले ही उसे करीब 375 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली बेच चुका है और फिलीपींस को इसकी अतिरिक्त प्रणालियों में भी रुचि है। इसके अलावा आकाश मिसाइल प्रणाली की संभावित बिक्री पर भी बातचीत हुई है। इसका सामरिक महत्व इसलिए बड़ा है क्योंकि फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ गंभीर समुद्री तनाव का सामना कर रहा है। भारत की मिसाइलें वहां पहुंचकर न केवल भारतीय रक्षा उद्योग की ताकत दिखाती हैं, बल्कि हिंद-प्रशांत में भारत की सुरक्षा भूमिका को भी मजबूत करती हैं।

• भारत-वियतनाम रक्षा संबंध

दूसरी बड़ी सफलता वियतनाम की है। मई 2026 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया और उसी दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वियतनाम के साथ सौदे की आधिकारिक पुष्टि हुई। यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वियतनाम दक्षिण चीन सागर में चीन के दबाव का सामना कर रहा है। भारत के लिए इसका अर्थ है कि उसकी मिसाइल और रक्षा तकनीक हिंद-प्रशांत के एक और महत्वपूर्ण तटीय देश तक पहुंच रही है।

• भारत-इंडोनेशिया रक्षा संबंध

इसके बाद इंडोनेशिया आता है। जुलाई 2026 में भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस के साथ-साथ अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और रक्षा तकनीक से जुड़े कई समझौते किए। रिपोर्टों के अनुसार इंडोनेशिया को दो ब्रह्मोस



बैटरियों की आपूर्ति का सौदा करीब 200 मिलियन डॉलर का है। इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह केवल हथियार बिक्री नहीं, बल्कि हिंद महासागर और दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री सुरक्षा ढांचे में भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत है।

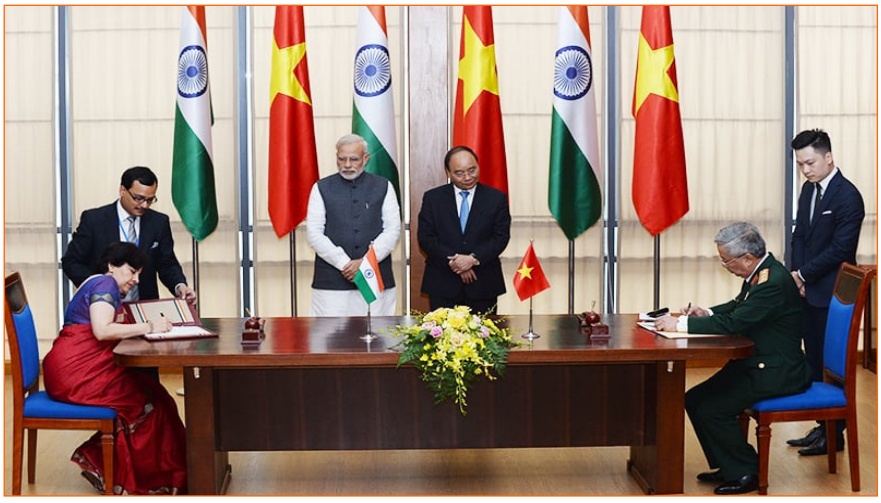
• भारत-आर्मेनिया रक्षा संबंध

वहीं आर्मेनिया भारत की रणनीतिक रक्षा नीति का एक अलग लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मोर्चा है। भारत ने उसे आकाश वायु रक्षा प्रणाली, पिनाका रॉकेट प्रणाली, स्वाति रडार और अन्य हथियार प्रणालियां उपलब्ध कराई हैं। 2022-24 के दौरान आर्मेनिया के हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 43 प्रतिशत बताई गई है। यह साझेदारी इसलिए भी अहम है क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान के साथ संघर्ष में है और अजरबैजान के पाकिस्तान तथा तुर्किये के साथ करीबी रक्षा संबंध हैं। इसलिए भारत-आर्मेनिया रक्षा सहयोग सीधे तौर पर उस क्षेत्रीय समीकरण में नई सैन्य धुरी बनाता है, जिसमें तुर्किये और पाकिस्तान पहले से सक्रिय हैं।

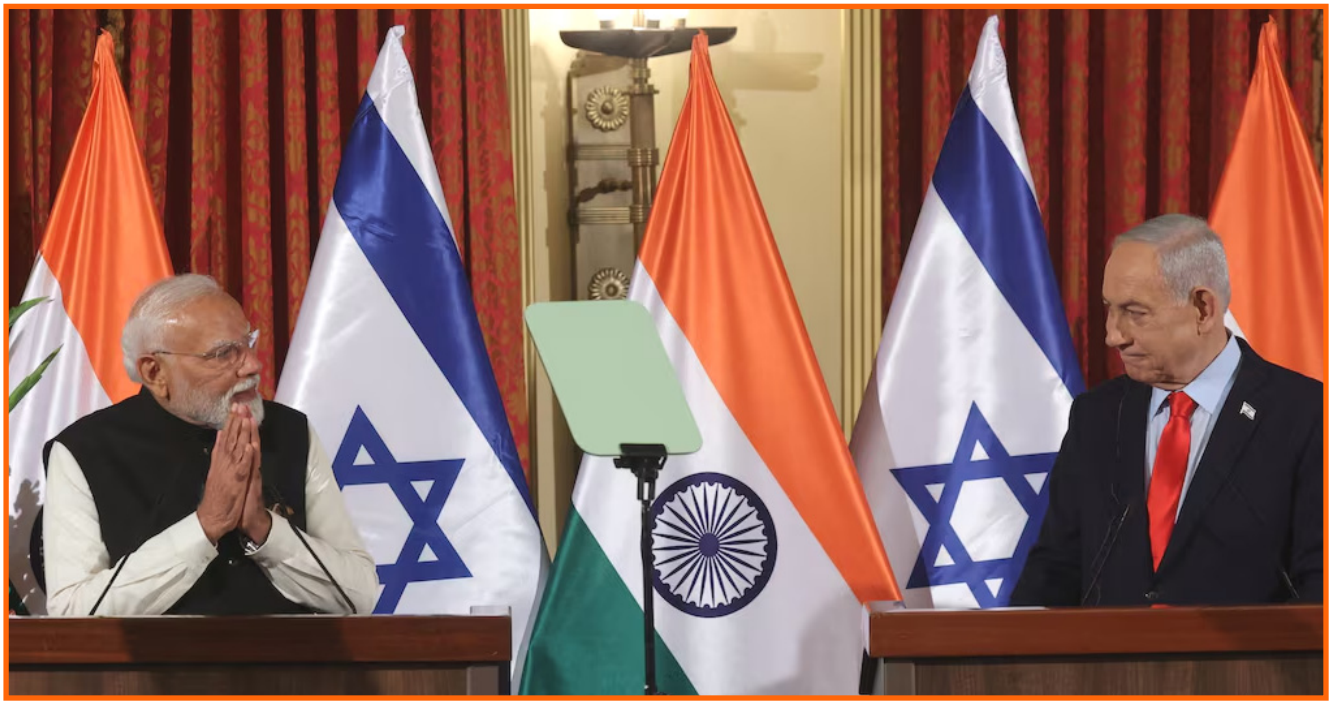
• भारत-यूएई रक्षा समझौता

वहीं भारत के लिए दूसरा बड़ा मोर्चा अरब जगत में उसकी बढ़ती रक्षा साझेदारी है। यूएई द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि इसी रणनीतिक समीकरण को बदल सकती है। यदि सौदा अंतिम रूप लेता है तो यह खाड़ी में भारत की शक्तिशाली उपस्थिति होगी। इससे तुर्की के ड्रोन और मिसाइल निर्यात को चुनौती मिल सकती है तथा यूएई को अपनी रक्षा क्षमता में नया विकल्प मिलेगा। पाकिस्तान के लिए यह बड़ा रणनीतिक झटका बन सकता है। एक तरफ वह तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर नया रक्षा मोर्चा मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत यूएई के साथ ब्रह्मोस जैसे अत्याधुनिक

हथियारों के सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर यह सौदा हुआ, तो अरब सागर और ओमान की खाड़ी में पाकिस्तान की नौसैनिक रणनीति पर दबाव बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, यूएई के बाद सऊदी अरब जैसे दूसरे खाड़ी देश भी भारत की रक्षा तकनीक में रुचि ले सकते हैं। साथ ही चूंकि यूएई फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और अरब सागर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति में है। ऐसे में भारतीय लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता यूएई को तुर्किये या पाकिस्तान पर निर्भर हुए बिना अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाने का विकल्प दे सकती है। यही वह बिंदु है जहां पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी गठजोड़ की काट साफ दिखाई देती है। सऊदी अरब को पाकिस्तान से सैन्य मानवबल और परमाणु प्रतिरोध की छाया मिलती है, तुर्किये से ड्रोन, मिसाइल और रक्षा उद्योग की ताकत मिलती है। लेकिन भारत यूएई जैसे खाड़ी देश को अलग रक्षा विकल्प दे सकता है। दूसरी तरफ फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया में भारतीय मिसाइलों की मौजूदगी हिंद-प्रशांत में भारत की समुद्री पहुंच बढ़ाती है, जबकि आर्मेनिया के साथ सहयोग तुर्किये-पाकिस्तान समर्थित क्षेत्रीय समीकरण को दूसरी दिशा से चुनौती देता है। इसलिए पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी गठजोड़ का जवाब भारत किसी एक नए सैन्य गठबंधन से देने की बजाय कई दिशाओं में दे रहा है। इजराइल से अत्याधुनिक तकनीक, फ्रांस से उच्चस्तरीय रक्षा औद्योगिक सहयोग, यूएई से खाड़ी में रणनीतिक पहुंच और फिलीपींस-वियतनाम-इंडोनेशिया के जरिए हिंद-प्रशांत में मिसाइल तथा समुद्री सुरक्षा नेटवर्क। यही भारत की असली रणनीतिक बढ़त है। यानी एक गठजोड़ के सामने दूसरा गठजोड़ खड़ा करने की बजाय भारत ने साझेदारियों का ऐसा जाल बिछाना शुरू किया है जिसमें पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब को हर दिशा में अलग-अलग रणनीतिक समीकरणों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल, एक चीज स्पष्ट है कि पाकिस्तान अगर डाल-डाल चलने की कोशिश कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि भारत पहले से पात-पात पर अपनी रणनीतिक मौजूदगी दर्ज करा रहा है।







एक देश, अनेक शिक्षा प्रणालियाँ.!

• क्या समान अवसर केवल संविधान की किताबों तक सीमित है?



सी एम जैन

भारत को अक्सर 'विविधताओं का देश' कहा जाता है। भाषाएँ अलग हैं, पहनावे अलग हैं, संस्कृतियाँ अलग हैं और जीवन-शैली भी अलग-अलग है। यही विविधता भारत की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा है, जिसे हमने शायद कभी गंभीरता से पूछने की कोशिश ही नहीं की—क्या शिक्षा भी विविधता का विषय होनी चाहिए, या समान अवसर का? आज भारत का हर बच्चा चाहे राजस्थान में जन्मा हो, बिहार में, गुजरात में, तमिलनाडु में या असम में—वह अंततः उसी भारत का नागरिक है। आगे चलकर वही बच्चा UPSC देगा, वही JEE और NEET देगा, वही सेना में भर्ती होगा, वही न्यायपालिका, प्रशासन, विज्ञान, उद्योग और राजनीति में अपनी जगह बनाएगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ सबके लिए समान हैं, लेकिन उन प्रतियोगिताओं तक पहुँचने का रास्ता सबके लिए समान नहीं है। यही भारतीय शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास है। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है। नीति-निर्देशक तत्व राज्य से अपेक्षा करते हैं कि वह समान अवसर उपलब्ध कराए। लेकिन व्यवहार में भारत की शिक्षा व्यवस्था अनेक परतों में बँटी हुई दिखाई देती है। कहीं राज्य बोर्ड, कहीं CBSE, कहीं ICSE, कहीं अलग-अलग क्षेत्रीय पाठ्यक्रम। परिणाम यह है कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चों का शैक्षणिक आधार केवल इसलिए अलग हो सकता है क्योंकि उनका जन्म अलग-अलग राज्यों में हुआ। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि राज्यों को अपनी भाषा, संस्कृति या इतिहास पढ़ाने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। होना चाहिए, और अवश्य होना चाहिए। भारत की विविधता का सम्मान लोकतंत्र की मूल भावना है। प्रश्न यह है कि क्या गणित, विज्ञान, संविधान, नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था, डिजिटल साक्षरता और बुनियादी जीवन-कौशल जैसे विषयों का न्यूनतम स्तर भी राज्य-राज्य में अलग होना चाहिए? जब राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्नपत्र समान होता है, तब तैयारी की बुनियाद अलग क्यों है? यदि अंतिम दौड़ एक ही ट्रैक पर होनी है, तो शुरुआती रेखा अलग-अलग क्यों खींची गई है? शिक्षा विशेषज्ञ वर्षों से इस ओर ध्यान दिलाते रहे हैं कि भारत में केवल पाठ्यक्रम ही नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता भी अत्यंत असमान है। कहीं प्रयोगशालाएँ हैं, कहीं केवल नाम मात्र की। कहीं प्रशिक्षित शिक्षक हैं, कहीं वर्षों से रिक्त पद। कहीं डिजिटल बोर्ड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रयोगशालाएँ हैं, तो कहीं बच्चों के पास बैठने के लिए पर्याप्त बेंच तक नहीं। ऐसे में केवल 'समान परीक्षा' की बात करना, समान अवसर की गारंटी नहीं बन जाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। बुनियादी साक्षरता, कौशल विकास, बहुभाषिकता और लचीले पाठ्यक्रम जैसे विचार स्वागतयोग्य हैं। लेकिन आज भी भारत में ऐसा कोई राष्ट्रीय न्यूनतम शैक्षणिक मानक नहीं है, जो यह सुनिश्चित करे कि देश के हर बच्चे ने कम-से-कम समान बुनियादी ज्ञान प्राप्त किया है। यही वह खाली स्थान है, जिस पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। समस्या केवल पाठ्यक्रम की नहीं है। किताबें अलग, उनकी कीमतें अलग, निजी विद्यालयों की फीस अलग, यूनिफॉर्म की व्यवस्था अलग, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता अलग। कई स्थानों पर अभिभावकों को विद्यालय द्वारा निर्धारित विशेष दुकानों से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती हैं। शिक्षा धीरे-धीरे अधिकार से अधिक बाज़ार का विषय बनती दिखाई देती है। यदि दो समान आय वाले परिवार अलग-अलग राज्यों में रहते हैं, तो संभव है कि उनके बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च और मिलने वाली गुणवत्ता दोनों अलग हों। यहाँ एक महत्वपूर्ण आपत्ति भी सामने आती है। कई लोग कहते हैं कि भारत जैसा विविध देश एक समान शिक्षा व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता। राज्यों की अपनी ऐतिहासिक, भाषाई और सांस्कृतिक आवश्यकताएँ हैं। यह तर्क महत्वपूर्ण है और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

वास्तव में किसी भी सुधार का उद्देश्य राज्यों की पहचान समाप्त करना नहीं होना चाहिए।

इसीलिए समाधान 'One Nation, One Syllabus' नहीं, बल्कि One Nation, One Minimum Education Standard' हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तमिलनाडु राजस्थान का इतिहास पढ़ाए या राजस्थान के विद्यालय मलयालम पढ़ाएँ। इसका अर्थ यह है कि देश का प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी भी बोर्ड में पढ़ता हो, कम-से-कम गणित, विज्ञान, संविधान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास की मूल रूपरेखा, अर्थव्यवस्था, डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण और जीवन-कौशल का एक समान राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करे। इसके ऊपर राज्य अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति, भूगोल और स्थानीय इतिहास पढ़ाएँ। विविधता भी बचे और समान अवसर भी। ऐसी व्यवस्था केवल छात्रों के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए लाभकारी होगी। इससे राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में आधारभूत असमानता कम होगी। राज्यों के बीच शैक्षणिक तुलना सरल होगी। शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन अधिक वस्तुनिष्ठ हो सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण–किसी बच्चे का भविष्य उसके जन्मस्थान से कम और उसकी प्रतिभा व मेहनत से अधिक निर्धारित होगा। इस चर्चा में फीस का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा यदि अधिकार है, तो उसकी पहुँच भी समान होनी चाहिए। यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं कि देश के हर निजी विद्यालय की फीस एक जैसी हो, क्योंकि भूमि, वेतन और संचालन लागत अलग-अलग हैं। लेकिन यह अवश्य संभव है कि फीस निर्धारण के लिए पारदर्शी राष्ट्रीय मानक हों, मनमानी वृद्धि पर नियंत्रण हो और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सहायता की प्रभावी व्यवस्था हो। शिक्षा का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, नागरिक बनाना होना चाहिए। यूनिफॉर्म के प्रश्न पर भी बहस आवश्यक है। पूरे देश में एक जैसी पोशाक व्यावहारिक न हो, लेकिन कम-से-कम ऐसा ड्रेस कोड विकसित किया जा सकता है जो अनावश्यक आर्थिक बोझ कम करे। यूनिफॉर्म किसी एक विक्रेता से खरीदने की बाध्यता समाप्त हो और अभिभावकों को खुले बाज़ार से निर्धारित मानक के अनुसार वस्त्र खरीदने की स्वतंत्रता मिले। इससे शिक्षा से जुड़े अनेक छोटे-छोटे आर्थिक शोषण स्वतः समाप्त हो सकते हैं। आज भारत 'विश्वगुरु' बनने की आकांक्षा रखता है। लेकिन कोई भी राष्ट्र अपनी शिक्षा व्यवस्था से ऊपर नहीं उठ सकता। विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं ने पहले अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, उसके बाद विज्ञान, उद्योग और नवाचार में नेतृत्व प्राप्त किया। यदि भारत को वास्तव में ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनना है, तो सबसे पहले उसे अपने बच्चों के लिए समान प्रारंभिक अवसर सुनिश्चित करने होंगे। यह लेख किसी राज्य के विरुद्ध नहीं है, किसी बोर्ड के विरुद्ध नहीं है और न ही किसी सरकार के विरुद्ध। यह केवल एक प्रश्न उठाता है–क्या भारत के बच्चों को कम-से-कम समान बुनियादी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? यदि उत्तर 'हाँ' है, तो अब बहस केवल शिक्षा नीति पर नहीं, बल्कि शिक्षा समानता पर होनी चाहिए। शायद समय आ गया है कि देश National Minimum Education Standard' पर गंभीर राष्ट्रीय विमर्श शुरू करे–ऐसा मानक जो राज्यों की विविधता का सम्मान करे, लेकिन बच्चों के भविष्य में असमानता न पैदा करे।

क्योंकि अंततः प्रश्न केवल शिक्षा का नहीं है। प्रश्न उस भारत का है, जहाँ एक बच्चे की सफलता उसकी प्रतिभा और परिश्रम से तय हो–न कि उसके पिन कोड, बोर्ड या राज्य से। और शायद लोकतंत्र में इससे बड़ा प्रश्न कोई नहीं हो सकता।

● बुनियादी साक्षरता, कौशल विकास, बहुभाषिकता और लचीले पाठ्यक्रम जैसे विचार स्वागतयोग्य हैं। लेकिन आज भी भारत में ऐसा कोई राष्ट्रीय न्यूनतम शैक्षणिक मानक नहीं है, जो यह सुनिश्चित करे कि देश के हर बच्चे ने कम-से-कम समान बुनियादी ज्ञान प्राप्त किया है। यही वह खाली स्थान है, जिस पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। समस्या केवल पाठ्यक्रम की नहीं है। किताबें अलग, उनकी कीमतें अलग, निजी विद्यालयों की फीस अलग, यूनिफॉर्म की व्यवस्था अलग, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता अलग। कई स्थानों पर अभिभावकों को विद्यालय द्वारा निर्धारित विशेष दुकानों से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती हैं।



वित्तीय अनुशासन और परिचालन दूरदर्शिता ने SAIL के वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के मुनाफे में भारी उछाल लाया।

सरोज वार्ता/संवाददाता



SAIL का वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही का प्रदर्शन केवल वार्षिक आधार पर मुनाफे में हुई तीव्र वृद्धि को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह वित्तीय सूझबूझ और परिचालन दूरदर्शिता के मेल से प्राप्त परिणामों को भी दर्शाता है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में SAIL के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. अशोक कुमार पांडा ने कहा, 'यह प्रदर्शन SAIL की एकीकृत रणनीति की मजबूती को दर्शाता है। मध्य पूर्व में अस्थिरता के कारण उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, हमने वित्तीय विवेक और सक्रिय परिचालन उपायों के संयोजन से लचीलापन प्रदर्शित किया। तिमाही के दौरान प्रदर्शन दक्षता सुधार की दिशा में सचेत प्रयास को दर्शाता है। कंपनी का नकदी प्रवाह प्रबंधन के प्रति अनुशासित दृष्टिकोण, सख्त वित्तीय नियंत्रण और कार्यशील पूंजी प्रबंधन में सुधार भी उतना ही महत्वपूर्ण था। 'SAIL द्वारा अपनाई गई विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन रणनीति के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, 'पहली तिमाही के दौरान, कंपनी ने अपनी दीर्घकालिक वित्तीय विश्वसनीयता और नकदी प्रवाह एवं ऋण प्रबंधन में और सुधार के माध्यम से उधार को नियंत्रित किया और उधार की लागत को कम किया। तरलता मजबूत बनी रही, और ऋण-इक्विटी अनुपात तथा शुद्ध ऋण-EBITD प्रोफाइल दोनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो लाभप्रदता बनाए रखते हुए ऋण जोखिम को कम करने में SAIL की सफलता को दर्शाता है। ' वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी के उत्पाद मिश्रण और निवेश प्राथमिकताओं में प्रगति देखी गई। कुल विक्रय योग्य इस्पात में तैयार इस्पात का अनुपात पिछले वर्ष की इसी अवधि के 86% से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 89% हो गया, जो कंपनी के समग्र उत्पाद समूह में अर्ध-तैयार इस्पात की मात्रा में क्रमिक कमी को दर्शाता है। मूल्यवर्धित इस्पात प्रेषण का प्रतिशत भी पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 7.5% बढ़ा, जो गुणवत्ता-आधारित विकास पर SAIL के फोकस को और मजबूत करता है। साथ ही, पूंजीगत व्यय (CAPE) लक्ष्य से अधिक होकर 2,306 करोड़ से 2,575 करोड़ हो गया, जो रणनीतिक निवेशों के प्रति कंपनी की मजबूत प्रतिबद्धता और क्षमता विस्तार एवं आधुनिकीकरण की दिशा में संसाधनों के सक्रिय आवंटन को उजागर करता है। इस तिमाही में SAIL की रणनीति को परिचालन क्षमता में परिणत करने की क्षमता भी प्रदर्शित हुई। ब्लास्ट फर्नेस की उत्पादकता में सुधार हुआ, लौह मिश्र धातुओं और फ्लक्स की खपत को अनुकूलित करके इस्पात निर्माण की लागत को कम किया गया, और आगामी तिमाहियों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित पूंजीगत मरम्मत कार्यों को समय से पहले ही पूरा कर लिया गया । डॉ. पांडा ने आगे बताया कि 'परिचालन संबंधी दूरदर्शिता पर हमारे ध्यान ने आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद निर्बाध प्रदर्शन सुनिश्चित किया। स्वदेशी और बाहरी स्रोतों के संतुलित मिश्रण के माध्यम से चूना पत्थर की आवश्यकताओं को पूरा किया गया, जबकि प्रोपेन गैस के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं ने निरंतरता को सुरक्षित रखा। ' खनन कार्यों पर केंद्रित प्रयासों से झरिया की आंतरिक खदानों की पूरी क्षमता का दोहन हुआ और महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। लौह अयस्क के बढ़े हुए उत्पादन से कंपनी अपनी आंतरिक कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम हुई, साथ ही अतिरिक्त अयस्क को घरेलू बाजार में बेचने में भी सफल रही। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में लौह अयस्क की बिक्री में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 269% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। इस असाधारण प्रदर्शन ने कंपनी के मुनाफे को काफी बढ़ाया और झरिया के एकीकृत व्यापार मॉडल की रणनीतिक मजबूती को रेखांकित किया, जिसमें खनन और इस्पात मूल्य श्रृंखला में मूल्य सृजन सीधे तौर पर बेहतर परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में परिणत होता है। कुल मिलाकर, ये घटनाक्रम इस बात को रेखांकित करते हैं कि SAIL न केवल वित्तीय मजबूती प्रदान कर रहा है, बल्कि अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को भी नया रूप दे रहा है और भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है - जो एक अस्थिर वैश्विक वातावरण में निरंतर प्रतिस्पर्धात्मकता की नींव रख रहा है।

आरईसी और पीएफसी ने 2,400 मेगावाट मेजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-II के लिए एमयूएनपीएल के साथ 26,850 करोड़ के साझा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

सरोज वार्ता/संवाददाता



आरईसी लिमिटेड और पीएफसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसई और प्रमुख आधारभूत संरचना वित्तपोषण एनबीएफसी, ने मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड (एमयूएनपीएल) के साथ सामान्य ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) के बीच 50:50 संयुक्त उद्यम है। इस समझौते के तहत कुल 26,850 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) प्रणाली के साथ स्टेज-II (3×800 मेगावाट) के तहत 800 मेगावाट की 2400 मेगावाट की मेजा टीपीपी स्टेज-II अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल इकाइयों की स्थापना के लिए दिया जाएगा, जिसकी अनुमानित परियोजना पूर्णता लागत 38,357.81 करोड़ रुपये है। ऋण दस्तावेजों पर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में एमयूएनपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री श्रीनिवास राव गद्दामनुगु, आरईसी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के मुख्य महाप्रबंधक श्री शंभू शंकर गुप्ता और पीएफसी की जीएम सुश्री शैली गुप्ता ने एमयूएनपीएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री अंगशु बरुआ, पीएफसी के कार्यकारी निदेशक श्री एच. के. दास और आरईसी के कार्यकारी निदेशक श्री डी. बी. लोंधे की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। प्रस्तावित 3×800 MW मेजा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (स्टेज II) एक साथ कई फायदे लेकर आएगा। यह उत्तर प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, घरों, खेतों और उद्योगों के लिए भरोसेमंद बिजली सुनिश्चित करेगा और राज्य के बड़े विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। आधुनिक तकनीक पुराने संयंत्रों की तुलना में कोयले की खपत और उत्सर्जन को कम करती है, जिससे यह अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनता है। इससे निर्माण और संचालन के दौरान हज़ारों नौकरियां पैदा होंगी, प्रयागराज की मेजा तहसील में स्थानीय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा, और औद्योगिक गलियारों, विनिर्माण क्लस्टरों और शहरी विस्तार के लिए निरंतर बिजली मिलेगी।



आरईसी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.25 प्रति शेयर का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया : पिछली तिमाही से पीएटी में 23% की वृद्धि



सरोज वार्ता/संवाददाता

एक गतिशील परिचालन वातावरण के बावजूद, आरईसी ने 3.34% का स्वस्थ NIM बनाए रखा, जो इसके ऋण पोर्टफोलियो की मजबूती और अनुशासित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, कंपनी ने 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए 63.04 प्रति शेयर का वार्षिक ईपीएस प्रदान किया, जो इसके मजबूत आय प्रदर्शन को रेखांकित करता है। गतिशील परिचालन माहौल के बावजूद, आरईसी ने 3.34% का स्वस्थ NIM कायम रखा, जो उसके ऋण पोर्टफोलियो और अनुशासित वित्तीय प्रबंधन की ताकत को दर्शाता है। नतीजतन, कंपनी ने 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए प्रति शेयर 63.04 का वार्षिक ईपीएस दिया, जो उसके मजबूत आय प्रदर्शन को रेखांकित करता है। 30 जून, 2026 तक आरईसी का स्टैंडअलोन ऋण पोर्टफोलियो 5.90 लाख करोड़ था, जो भारत में किसी भी सीपीएसयू-एनबीएफसी के लिए सबसे अधिक है, जो इसके ऋण संचालन की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। मुनाफे में वृद्धि के कारण, 30 जून, 2026 तक शुद्ध संपत्ति (नेट वर्थ) सालाना आधार पर 15% बढ़कर 91,836 करोड़ हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में मजबूत वृद्धि जारी रही और यह बढ़कर 78,596 करोड़ हो गया, जो कुल ऋण संरचना का 13.32% है। यह टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और भारत में हरित ऊर्जा के विकास को गति देने के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक पोर्टफोलियो बढ़कर ?59,289 करोड़ हो गया है, जो कुल ऋण संपत्ति का 10% से अधिक है। एसेट क्वालिटी में सुधार के निरंतर प्रयासों से प्रेरित होकर, कंपनी ने अपने कुल ऋण पोर्टफोलियो में स्टेज-3 ऋण एसेट के अनुपात को लगभग शून्य स्तर यानी 0.11% तक कम कर दिया है। भविष्य के विकास को समर्थन देने के पर्याप्त अवसर का संकेत देते हुए, कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो 30 जून, 2026 तक आरबीआई द्वारा अनिवार्य 15% के रेगुलेटरी मिनिमम के मुकाबले आरामदायक 23.06% पर है। अपने निरंतर लाभांश वितरण रिकॉर्ड और शेयरधारकों का रिटर्न बढ़ाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 4.25 का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया है। भारतीय बिजली क्षेत्र के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों ने बिजली उपयोगिताओं की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में योगदान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत हुआ है और परिणामस्वरूप प्रावधान आवश्यकताओं में कमी आई है। अपने ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, आरईसी ने ऋण दरों को तर्कसंगत बनाकर उधारकर्ताओं के साथ इन लाभों को सक्रिय रूप से साझा किया, जिसके परिणामस्वरूप Q1-FY 2026-27 में 9.55% की उपज प्राप्त हुई। कंपनी को तीसरे सालाना भारत एनबीएफसी और फिनटेक समिट और अवार्ड्स 2026 में 'NBFC ऑफ़ द ईयर' अवार्ड और दूसरे भारत पीएसयू मंथन और एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 में 'AI और GenAI एडॉप्शन एक्सीलेंस अवार्ड' से सम्मानित किया गया, जो इसके मज़बूत व्यावसायिक प्रदर्शन, डिजिटल नवाचार और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने में इसके नेतृत्व को रेखांकित करता है। आरईसी लिमिटेड देश में पारंपरिक ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे व लॉजिस्टिक्स विकास में लक्षित निवेश के माध्यम से रणनीतिक रूप से अपने व्यावसायिक पदचिह्न का विस्तार कर रहा है, साथ ही यह देश में सरकारी कार्यक्रमों, नीतियों और सुधारों को लागू करने और दीर्घकालिक विकास को लगातार बढ़ावा देने में भारत सरकार का एक रणनीतिक भागीदार भी है।

परिचालन और वित्तीय मुख्य विशेषताएं: क्यू1 एफाई27 बनाम क्यू4 एफवाई26

- शुद्ध ब्याज आय: 5,212 करोड़ बनाम 4,961 करोड़, 5% की वृद्धि
- शुद्ध लाभ: 4,149 करोड़ बनाम 3,362 करोड़, 23% की वृद्धि

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत मंत्री से ऊर्जा परियोजनाओं एवं पिटकुल की एडीबी सहायतित पारेषण परियोजना पर की चर्चा



सरोज वार्ता/संवाददाता



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर उत्तराखण्ड की ऊर्जा आवश्यकताओं, जल विद्युत परियोजनाओं, पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तथा पिटकुल की एडीबी (ष्ठक्क) सहायतित पारेषण परियोजना सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने में दिए जा रहे सहयोग के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार एल-नीनो की संभावित परिस्थितियों, वर्षा में कमी तथा जलाशयों में कम जलागम के कारण आगामी महीनों में जल विद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वहीं चारधाम यात्रा एवं आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत मांग में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने जुलाई 2026 की शेष अवधि के लिए 150 मेगावाट तथा अगस्त 2026 के लिए 200 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत केंद्रीय पूल से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड को पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में लगभग 10 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता के विकास के लिए आगामी पांच वर्षों में 7,800 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता अथवा वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं और ग्रिड स्थिरता को देखते हुए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्वीकृत क्षमता 500 मेगावाट आवर से बढ़ाकर 665 मेगावाट आवर किए जाने तथा उसके अनुरूप वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने बैठक में पिटकुल की 3,638.26 करोड़ रुपये (₹ 425.78 मिलियन) लागत वाली एडीबी सहायतित पारेषण परियोजना के विषय पर भी चर्चा की। उन्होंने अनुरोध किया कि इस परियोजना के लिए मूल 80:20 एडीबी ऋण एवं राज्यांश की वित्तीय व्यवस्था को यथावत रखा जाए। उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत 2,910.61 करोड़ रुपये (₹ 340.62 मिलियन) का एडीबी ऋण प्रस्तावित है, जिसे उत्तराखण्ड जैसे विशेष श्रेणी के हिमालयी राज्य के लिए निर्धारित वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना को तकनीकी रूप से उपयुक्त माना गया है तथा विद्युत मंत्रालय ने भी एडीबी सहायता पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। हालांकि एडीबी हिस्सेदारी को 60 प्रतिशत तक सीमित करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि वित्तीय पैटर्न में परिवर्तन किया जाता है तो उत्तराखण्ड को विशेष श्रेणी राज्य के रूप में मिलने वाले वित्तीय लाभ प्रभावित होंगे। इसलिए मूल 80:20 वित्तीय व्यवस्था को बरकरार रखते हुए परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एवं ऊर्जा आत्मनिर्भरता के संकल्प को साकार करने में उत्तराखण्ड की जल विद्युत क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का सकारात्मक सहयोग राज्य के ऊर्जा क्षेत्र, आधारभूत संरचना तथा सतत विकास को नई गति प्रदान करेगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

बदलते रिश्तों से नए भारत की बदलती तस्वीर



रविंद्र राजपूत



21वीं सदी के भारत ने तकनीक, व्यापार और विज्ञान के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व छलांग लगाई है, वह वाकई अद्भुत है। जिस सुविधायुक्त जीवन की कल्पना हमारी पुरानी पीढ़ियों के लिए एक सपना थी, वह आज हमारी दिनचर्या बन चुका है। लेकिन इस भौतिक प्रगति की जो भारी कीमत हमारा समाज चुका रहा है, वह है–रिश्तों का खोता वजूद और मानसिक शांति।

•बदलते रिश्तों के मुख्य कारण

तुलना और असंतोषः सोशल मीडिया और बढ़ते भौतिकवाद ने लोगों के भीतर 'मेरे पास क्या नहीं है' की अंधी होड़ भर दी है। 'सामने वाले ने मेरे लिए क्या किया?' की सोच ने निस्वार्थ प्रेम की जगह ले ली है। संवादहीनता और डिजिटल दूरीः एक ही छत के नीचे रहते हुए भी लोग अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन में उलझे हैं। संवाद बंद होने से छोटी-छोटी बातें बड़ी गलतफहमियों का रूप ले लेती हैं। सहनशीलता और धैर्य का अभावः आज छोटी-छोटी बातों पर अहम आड़े आ जाता है। रिश्तों को सहेजने से ज्यादा प्राथमिकता 'खुद को सही साबित करने' को दी जाने लगी है। दिखावा और बढ़ता तनावः दूसरों को प्रभावित करने की होड़ में क्षमता से अधिक खर्च करना सीधे मानसिक दबाव को जन्म देता है, जिससे परिवारों में रोज़ाना के क्लेश बढ़ते हैं।

•गुस्से का चक्र और जीवन पर प्रभाव

पारिवारिक तनाव का दायरा केवल घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक खतरनाक 'चैन रिएक्शन' बनाता हैः

पारिवारिक कलह -->मानसिक असंतुलन -->कार्यस्थल पर चिड़चिड़ापन व गुस्सा -->सहकर्मियों पर भड़ास -->समाज में तनाव

दफ़्तर का तनाव जब किसी अधिकारी से छोटे कर्मचारी, चपरासी और फिर घर के बेकसूर सदस्यों तक पहुँचता है, तो यह पूरे माहौल का संतुलन बिगाड़ देता है। जब तक इंसान को यह समझ आता है कि झगड़े की वजह कितनी मामूली थी, तब तक रिश्तों में इतनी खटास आ चुकी होती है कि पहले जैसी मिठास लौटाना मुश्किल हो जाता है।

•बदलाव का मूल मंत्रः 'संतोष'

इस पूरी समस्या का सबसे सीधा और सटीक समाधान एक ही शब्द में छिपा है–'संतोष'। संतोष कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक मानसिक कला है। जब हम जो है उसमें खुश रहना सीख लेते हैं, तो बेवजह की भागदौड़ और तनाव अपने आप खत्म हो जातेहैं।

सुधार के व्यावहारिक कदम

•1. अपेक्षित प्रतिक्रिया दें, तुरंत रिएक्ट न करें: गुस्सा आने पर तुरंत भड़ास निकालने के बजाय कुछ सेकंड का ठहराव लें।

•2. डिजिटल डिटॉक्स और संवादः दिन का कुछ समय परिवार के साथ बिना फोन के बिताएं और खुलकर बात करें।

•3. शिकायतें छोड़ें, स्वीकार्यता लाएं:'किसने क्या नहीं किया' के बजाय 'हमारे पास क्या है' पर ध्यान केंद्रित करें।

रिश्तों का नया सवेरा ...आया है
हर रिश्ते को फिर से समझने का वक्त आया है
आपस में खुशियाँ बाँटने का नया दौर आया है
इंतज़ार की घड़ियाँ अब तो खत्म हो आईं,
एक-दूजे से मिलने-मिलाने की बहारें आईं
कुछ करनी होंगी प्यार भरी बातें,
कुछ अनकही खामोशियों की सौगातें
फिर शुरू होंगी घर, सँवारने की बातें
संग बुनेंगे सपने, ऐसी हसीन होंगी रातें
खुद से ज़्यादा अपनों का सम्मान करना होगा
आने वाले हर पल को सुहाना बनाना होगा
एक-दूजे की खातिर थोड़ा झुकना भी होगा
रिश्तों की खातिर अपनी ज़िद को छोड़ना भी होगा
ज़िंदगी के इस लंबे और खूबसूरत सफ़र में,
हर मोड़ पर एक-दूजे का साथ निभाना होगा
जब भी रूठेगा कोई अपना बेवजह कभी,
दूजे को आगे बढ़कर प्यार से मनाना होगा
और जब कभी दफ़्तर से होंगे तुम लेट,
तो इंतज़ार की मिर्ची पर प्यार का मक्खन लगाना होगा

उपरोक्त पंक्ति में इंतज़ार की मिर्च पर मक्खन लगाने जैसी उपमा में जो आत्मीयता और हास्य है, वही वास्तव में टूटते रिश्तों को जोड़ने का असली मलहम है।

•पारिवारिक तालमेल से राष्ट्र निर्माण का सफर

किसी भी देश की नींव उसकी सड़कें या इमारतें नहीं, बल्कि उसके परिवार होते हैं। भारत केवल एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि अटूट पारिवारिक मूल्यों और समृद्ध संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है।

घर में प्रेम व सम्मान -->मानसिक शांति -->कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन -->मजबूत समाज -->विकसित भारत

जब व्यक्ति घर से मानसिक रूप से खुश और संतुष्ट निकलेगा, तो उसकी ऊर्जा, सोच और काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। नागरिकों की यही सकारात्मक ऊर्जा समाज को बेहतर बनाती है।यदि हम तकनीक के साथ-साथ अपने संस्कारों और रिश्तों की जड़ों को सींचना शुरू कर दें, तो देश की तस्वीर बेहद खूबसूरत और सशक्त बन सकती है और जब हर नागरिक जिम्मेदारी से अपनी भागीदारी निभाता है, तो देश को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता।

15 अगस्तआ रहा है...जश्न-ए-आज़ादी के पावन पर्व 'स्वतंत्रता दिवस' पर आइए, हमभारतवासी अपनी समृद्ध विरासत, मजबूत रिश्तों और महान परंपराओं को फिर से जीवंत करें और आने वाली पीढ़ियों को भी इस मुहिम का हिस्सा बनाएँताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें और राष्ट्रहित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। आज़ादी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि अपनी विरासत, संस्कृति और जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने का संकल्प है।

जहाँ हर व्यक्ति को सम्मान मिले,
हर रिश्ते में अपनापन हो,
हर परंपरा में गर्व हो,
और हर नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। आइए, मिलकर नया भारत बनाएँ जिसकी जड़ें मजबूत हों और जिसका भविष्य और भी उज्ज्वल हो।

प्रधानमंत्री मोदी से मिली प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, पुराल से बना कमल दिया, संगठनात्मक विषयों पर हुई चर्चा

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद मिलना जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षणः डॉ. अर्चना गुप्ता

सरोज वार्ता/संवाददाता



हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान डा. अर्चना गुप्ता ने ''पुराल'' से निर्मित कमल का पुष्प भेंट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। लगभग आधे घंटे तक चली इस आत्मीय मुलाकात में संगठनात्मक, सामाजिक और महिला सशक्तिकरण तथा विकसित भारत के संकल्प सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं प्रभावशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, उनका स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे जीवन का अत्यंत गौरवपूर्ण प्रेरणादायी क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद यह उनके सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर रहा। डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हरियाणा की नायब सरकार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, प्रत्येक कार्यकर्ता को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने तथा सेवा, सुशासन और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री द्वारा कही गई प्रत्येक बात को आत्मसात कर प्रदेश संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा जनसेवा के लिए स्वयं को पूरी निष्ठा से समर्पित करने का उनका संकल्प और मजबूत हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता केवल विचार नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प है। आज उनके साथ हुई मुलाकात में इस भावना को उन्होंने निकट से अनुभव किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का अक्षरशः पालन करते हुए भाजपा हरियाणा प्रदेश को संगठनात्मक रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी और महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत करेगी। डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि यह हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप हमारी माताएं और बहनें राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विज्ञान सहित हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दूरदर्शी नेतृत्व और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक निर्णय देश की आधी आबादी को वास्तविक अर्थों में सशक्त कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि यह विश्वास उनके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। वह इस जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगी तथा संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि हरियाणा भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। सेवा, संगठन और राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जन-जन तक मोदी और नायब सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन हरियाणा भाजपा के लिए नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नए संकल्प का आधार बनेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए प्रत्येक मार्गदर्शक शब्द को आत्मसात करते हुए उन्होंने प्रदेश संगठन और लोककल्याण के लिए स्वयं को पूर्ण समर्पित करने का संकल्प और अधिक दृढ़ किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के मूल मंत्र के साथ विकसित हरियाणा और विकसित भारत के निर्माण में पूरी निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपनी भूमिका निभाता रहेगा।

हरियाणा की महिलाओं के हुनर का प्रतीक बना ''पुराल'' से निर्मित कमल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने हरियाणा के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा पुराल (धान के अवशेष/प्राकृतिक रेशों) से हस्तनिर्मित कमल का फूल भेंट किया। यह कलात्मक स्मृति-चिन्ह हरियाणा की ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता, स्वदेशी शिल्प, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे नवाचार का सशक्त उदाहरण है। यह उपहार केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि वोकल फॉर लोकल, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी दर्शाता है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार ऐसे उत्पाद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ हरियाणा की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य कर रहे हैं।

खेल में अपनी प्रतिभा को पहचाने और भविष्य संवारें

सरोज वार्ता/ब्यूरो



एक समय था जब यह माना जाता था कि केवल पढ़ाई-लिखाई ही उज्ज्वल भविष्य और अच्छी नौकरी का मार्ग है। इसी सोच को दर्शाते हुए कहा जाता था- 'पढ़ोगे-लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे बनोगे खराब।' लेकिन आज का भारत इस धारणा को पूरी तरह बदल चुका है।इसलिए आज के दौर में यह कहना उचित नहीं होगा कि केवल पढ़ाई-लिखाई ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। यदि किसी में खेल के प्रति जुनून, अनुशासन और समर्पण है, तो वह खेलों के माध्यम से भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। शिक्षा और खेल, दोनों मिलकर व्यक्तित्व का समग्र विकास करते हैं तथा जीवन में सफलता के नए द्वार खोलते हैं। खेल केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास, अनुशासन और सफलता की ऐसी पाठशाला है, जहाँ से भविष्य के विजेता तैयार होते हैं। आज खेलों में करियर की असीम संभावनाएँ हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान, रोजगार, आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक पहचान मिल रही है। ऐसे समय में प्रत्येक युवा के लिए आवश्यक है कि वह अपनी खेल प्रतिभा को पहचाने और उसे सही दिशा देकर अपने भविष्य को संवारे।हर बच्चे के भीतर कोई न कोई विशेष क्षमता होती है। किसी की गति उसे उत्कृष्ट धावक बनाती है तो किसी की फुर्ती कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल या अन्य खेलों में सफलता दिला सकती है। यदि प्रतिभा को समय पर प्रशिक्षण और अवसर मिले, तो वही खिलाड़ी प्रदेश और देश का गौरव बनता है।खेलों का सबसे बड़ा योगदान यह है कि वे जीवन के महत्वपूर्ण गुणों का विकास करते हैं। अनुशासन, धैर्य, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, समय प्रबंधन और संघर्ष का साहस खेल के मैदान में ही सीखा जाता है। यही गुण आगे चलकर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नींव रखते हैं। छत्तीसगढ़ में खेलों को नया स्वरूप देने की दिशा में राज्य शासन ने उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने, ग्रामीण और जनजातीय अंचलों के युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने तथा खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं। प्रदेश में आधुनिक खेल अधोसंरचना का विकास, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार, खेल अकादमियों को सुदृढ़ करना तथा विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसी के साथ ही इस वर्ष से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खेलों इंडिया ट्राइबल गेम्स का सफल आयोजन किया गया है। विशेष रूप से बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक जैसी अभिनव पहल ने खेलों को गाँव-गाँव तक पहुँचाया है। इन आयोजनों ने दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया है। परंपरागत खेलों के साथ आधुनिक खेलों को भी बढ़ावा देकर हजारों युवाओं, महिलाओं और बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। इन प्रतियोगिताओं ने यह साबित किया है कि अवसर मिलने पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं, ग्रामीण खेल आयोजनों, प्रतिभा खोज कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से नई प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, सम्मान और विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर कई पुरस्कार प्रदान करती है। जिसमे गुंडाधुर सम्मान शामिल है। यह छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार बस्तर के वीर नायक गुंडाधुर की स्मृति में, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। दूसरा महाराज प्रवीरचंद भंजदेव के नाम पर है। यह पुरस्कार विशेष रूप से तीरंदाजी के खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में खेल प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है, जिससे युवाओं में खेल का अवसर प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। वर्तमान में ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (ग्लासगो) में महिला 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। अमितेश कुजूर ने राष्ट्रमंडल खेल में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी प्रकार अन्य खिलाड़ियों ने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। आज खेल केवल खिलाड़ी बनने तक सीमित नहीं हैं। खेल प्रशिक्षक, फिटनेस विशेषज्ञ, खेल प्रबंधन, खेल विज्ञान, खेल पत्रकारिता और खेल प्रशासन जैसे अनेक क्षेत्रों में भी युवाओं के लिए रोजगार और करियर के नए अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए खेल को अब केवल शौक नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण के प्रभावी माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। अभिभावकों और शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की रुचि और क्षमता को पहचानें तथा उन्हें खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। पढ़ाई और खेल एक-दूसरे के पूरक हैं। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही उत्कृष्ट शिक्षा और सफल जीवन का आधार बनते हैं। आज जब डिजिटल दुनिया बच्चों को मैदान से दूर कर रही है, तब आवश्यकता है कि उन्हें फिर से खेल मैदानों की ओर प्रेरित किया जाए। मैदान में बिताया गया समय केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, सोच और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत बनाता है। खेल हमें सिखाते हैं कि हर जीत के पीछे निरंतर अभ्यास, अनुशासन और संघर्ष छिपा होता है। इसलिए अपनी प्रतिभा को पहचानिए, शासन, प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अवसरों का भरपूर लाभ उठाइए और बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जैसे आयोजनों को अपने सपनों की उड़ान का मंच बनाइए। आज का खिलाड़ी ही कल का चौंपियन, प्रदेश का गौरव और देश का भविष्य है।

डिजिटल क्रांति की ओर छत्तीसगढ़



सरोज वार्ता/ब्यूरो

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा प्रदेश के नागरिकों को सुगम, त्वरित और पारदर्शी राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। 'वसुंधरा' परियोजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों के पुराने एवं वर्तमान राजस्व अभिलेखों का संपूर्ण डिजिटलीकरण, संरक्षण तथा प्रमाणीकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 'वसुंधरा परियोजना' के तहत राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे खसरा, बी-1 और ऋण पुस्तिका जैसे भूमि दस्तावेज कुछ ही सेकंड में व्हाट्सएप और ऑनलाइन माध्यमों से सुरक्षित व पारदर्शी रूप से नागरिकों को मिल रहे हैं।

● दंतेवाड़ा का सफल मॉडल बना प्रेरणा

इस महत्वाकांक्षी योजना की नींव दंतेवाड़ा जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए मॉडल पर रखी गई है। दंतेवाड़ा में पिछले एक वर्ष के दौरान 12 हजार से अधिक नागरिकों ने कियोस्क सेवाओं का लाभ उठाया और 15 हजार से अधिक जाति प्रमाण-पत्र मात्र एक से दो दिनों में जारी किए गए। इसके साथ ही सैकड़ों विवादित मामलों का त्वरित निराकरण संभव हुआ और अभिलेखों में छेड़छाड़ का एक भी मामला सामने नहीं आया।

● 12.89 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण का विशाल लक्ष्य

दंतेवाड़ा के इसी सफल प्रयोग के आधार पर अब पूरे राज्य में लगभग 12 करोड़ 89 लाख पृष्ठों के विभिन्न राजस्व अभिलेखों को डिजिटाइज़ करने का विस्तृत खाका तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत 22.72 करोड़ रुपए की लागत से 5.68 करोड़ पृष्ठ खसरा पांचसाला, 11.77 करोड़ रुपए की लागत से 2.94 करोड़ पृष्ठ क्र-1 रिकॉर्ड, 9.98 करोड़ रुपए की लागत से 2.49 करोड़ पृष्ठ नामांतरण व संशोधन पंजी, 2.13 करोड़ रुपए की लागत से 53.16 लाख पृष्ठ मिसल पंजी और 1.89 करोड़ रुपए की लागत से 47.29 लाख पृष्ठ अधिकार अभिलेख शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निस्तार पत्रक, वाजिब-उल-अर्ज, रीनंबरिंग सूची, साधारण खसरा, नजूल शीट एवं व्यवर्तन पंजी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा।

● मजबूत वित्तीय संरचना और चरणबद्ध समयसीमा

इस विशाल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 65.41 करोड़ रुपए की कुल एकमुश्त पूंजीगत लागत और 50 लाख रूपए प्रति वर्ष का परिचालन व्यय तय किया गया है, जिसकी वित्तीय व्यवस्था राज्य के अधोसंरचना मद और केंद्र सरकार की DILRMP 3.0 योजना से की जाएगी। योजना के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से अगले तीन महीनों के भीतर वसुंधरा पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा, जिसके बाद कार्यदायी एजेंसियों का चयन कर एक वर्ष के भीतर सभी अभिलेखों के डिजिटलीकरण और सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

● आधुनिकतम तकनीक से लैस और पूरी तरह सुरक्षित

'वसुंधरा' परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसमें आधुनिकतम तकनीकों का समावेश है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित OCR, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन और स्मार्ट सर्च इंजन की मदद से दशकों पुराने रिकॉर्ड भी पलक झपकते ही खोजे जा सकेंगे। वहीं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या हेरफेर को रोकने के लिए ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा, डिजिटल हस्ताक्षर और यूनिक क्यूआर बारकोड प्रणाली लागू की जाएगी। दस्तावेजों के ऑनलाइन होने से रिकॉर्ड में किसी भी तरह के अवैध बदलाव या छेड़छाड़ की गुंजाइश खत्म होना।

● नागरिकों को मिलेगी दफ्तरों के चक्करों से आजादी

इस योजना के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद वर्तमान में नकल प्राप्ति में लगने वाला 3 से 7 दिनों का समय घटकर मात्र कुछ मिनटों का रह जाएगा और यह सेवा नागरिकों को 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। घर बैठे कुछ ही पलों में जमीन के जरूरी दस्तावेज प्राप्त किया जा सकेगा । नागरिक अब वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, लोक सेवा केंद्रों और कियोस्क के माध्यम से घर बैठे प्रमाणित अभिलेख प्राप्त कर सकेंगे। सुगम ऑनलाइन पेमेंट गेटवे और अधिकारियों के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं से आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार का यह नवाचार न केवल भूमि विवादों और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह अंकुश लगाएगा, बल्कि राज्य में डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन के एक नए युग का सूत्रपात भी करेगा।

समृद्ध मध्यप्रदेश के लिए सेवा और सुशासन ही हमारा मूल विकास मंत्र : मुख्यमंत्री डॉ. यादव



सरोज वार्ता/ब्यूरो

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि नगर निगम जबलपुर अगले एक वर्ष में मेट्रोपोलिटन सिटी बनेगा। उन्होंने मौके पर ही संबंधितों (कमिश्नर, कलेक्टर एवं अन्य) को जल्द से जल्द जबलपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी का ड्रॉफ्ट प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सेवा हमारी सरकार का दायां और सुशासन बायां हाथ है। हम मध्यप्रदेश के विकास प्रदेश के नागरिकों की सुख-समृद्धि और सेवा के प्रति संकल्पित है। सेवा और सुशासन ही हमारे लिए समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण का मूल और वास्तविक विकास मंत्र है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने प्रदेश की जनता से विकास का सच्चा वादा किया है। आज प्रदेश में चहुंओर विकास की बहार है। 'सच्चा वादा, पक्का काम' हम जो भी कहते हैं, वो करके भी दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को जबलपुर के गीता भवन परिसर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-भूमिपूजन का 11 लाख पौधे लगाने के महा अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जबलपुर जिले को और भी कई सौगातें दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जबलपुर में एक 'फर्नीचर क्लस्टर' बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी को अब मध्यप्रदेश के एम्स (राज्यस्तरीय आयुर्विज्ञान संस्थान) के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जबलपुर और आसपास की परिधि मे स्थित नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों के विशेष आकर्षण के लिए जबलपुर में ही वाइल्ड एनीमल्स विजिबिलिटी की सुविधा विकास के लिए यहां मदन महल पहाड़ी के पास एक चिड़िया घर (जू) बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि जबलपुर जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सांदीपनि विद्यालय भी बनाये जायेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जबलपुर शहर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यहां करीब 397 करोड़ रूपए के 5 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगर निगम जबलपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण पर केन्द्रित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन कर यहां पात्र सैकड़ों रेहड़ी-पटरी-श्रमिक (स्ट्रीट वेंडर्स) हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल क्रेडिट कार्ड्स भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर शहर में 362.31 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 'अमृत 1.0' सीवेज परियोजना का शुभारंभ कर कठौंदा, ललपुर और तेवर में बने तीन बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जबलपुर की सिविल लाइन्स इलाके में 25 लाख रूपए की लागत से रजक समुदाय के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडर्न लॉन्ड्री एरिया का शुभारंभ कर गुरंदी बाजार क्षेत्र में 2.5 करोड़

● कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जबलपुर शहर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यहां करीब 397 करोड़ रूपए के 5 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगर निगम जबलपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण पर केन्द्रित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन कर यहां पात्र सैकड़ों रेहड़ी-पटरी-श्रमिक (स्ट्रीट वेंडर्स) हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल क्रेडिट कार्ड्स भी प्रदान किए।

रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक मत्स्य विक्रय केन्द्र का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर को 'पुण्य नगरी' की उपमा देते हुए कहा कि हमारे देश और प्रदेश में कई तरह से विकास कार्य चल रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का स्वर्णिम काल चल रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' से आकाशवाणी को एक नई पहचान दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप देश की 80 करोड़ आबादी को निःशुल्क राशन, पक्का मकान, निःशुल्क शौचालय, हर घर नल से जल, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के इलाज की निशुल्क सुविधा मिल रही है। रेहड़ी वाले छोटे व्यापारियों को पीएम स्वनिधि योजना में लाभ मिल रहा है। आज जबलपुर के अनेक हितग्राहियों को डिजिटल कार्ड प्रदान किए गए हैं। हर गरीब के जीवन को सुख के सूरज की रौशनी से प्रकाशित करने के लिये प्रतिबद्ध होकर राज्य सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 'सरकार का अर्थ सहकार' और 'सहकार का अर्थ परिवार' की सहायता करना है। दुनिया के सामने भारत वसुधैब कुटुम्बकम का एक आदर्श उदाहरण है। भारतीय परंपरा प्राचीनकाल से इसी भाव से आगे बढ़ती रही है। उन्होंने कहा कि अपने जंगलों को हराभरा रखने के लिए हम सभी जरूरी प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति के साथ रिश्ता और भी मजबूत बनाने के लिए आज जबलपुर से 11 लाख पौधे लगाने के लिए सघन पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन में ऋषि-मुनियो के समान होते हैं। पेड़ों से हमें स्वच्छ हवा मिलती है। यह सबको जीवन देते हैं। पौधरोपण के लिए नई जापानी 'मियावाकी पद्धति' से एक एकड़ भूमि पर 12 हजार पौधे लगाए जा सकते हैं। यह क्षेत्र तीन साल से कम अवधि में सघन वन बन जाता है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश में नदियों का मायका है। यहां हर-भरे सघन वन हैं। नदियां जंगलों को हराभरा रखती हैं। सभी को खुशहाली और आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। नर्मदा नदी से गुजरात और राजस्थान को भी समृद्धि मिलती है। चंबल और सोन जैसी नदियां गंगा-यमुना की धारा को रफ्तार देती हैं।

सब समान-सबको सम्मान - यूसीसी का यही आधार: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश की आजादी के बाद तत्कालीन सरकारों ने समाज को अपनी ही धारा और राजनीतिक नजरिए से देखा। उन्होंने धर्म के आधार पर लोगों में वर्ग विभेद किया। रहीम और रसखान की रचनाएं देखिए, जिनमें भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का चित्रण मिलता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार आने के बाद देश में कहीं भी सद्भाव नहीं बिगड़ा। उन्होंने कहा कि यह बदलते दौर का भारत है। मध्यप्रदेश सरकार ने हिंदू और मुस्लिम सहित सभी वर्गों के लिए एक समान कानून लागू करने का निर्णय लिया है। यूसीसी लागू करने के लिए राज्य सरकार ने 3 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे, जिसके बाद 10 लाख से अधिक सुझाव



यूसीसी समिति के पास आए। इन सुझावों में 74 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम बहनों ने यूसीसी लागू करने का समर्थन किया। 'सब समान-सबको सम्मान' देने के उद्देश्य से हमारी सरकार एक समान कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का लोक निर्माण विभाग देश में सबसे अच्छा काम करने वाला विभाग है। हमारी सरकार द्वारा लोक निर्माण क्षेत्र में हुए कई नए काम और नवाचार अब पूरे देश में लागू हो रहे हैं। मध्यप्रदेश ने ब्रिटिशकाल के राजमार्ग कानून और फायर सेफ्टी एक्ट में भी संशोधन कर लिया है।

प्रदेश में बन रहे हैं भव्य सांदीपनि विद्यालय, पुलिस विभाग में 18 हजार से अधिक पदों पर भर्ती:

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सांदीपनि विद्यालय भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता के प्रतीक हैं। हमारे बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा मिले, इसीलिए प्रदेशभर में भव्य सांदीपनि विद्यालय बनाए गए हैं। युवाओं का भविष्य संवारने के लिए हमने इसी साल 10 हजार शिक्षकों की भर्ती कर ली है। पुलिस विभाग में 18 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण वाले मसले का समाधान निकालकर अब तक राज्य के सभी विभागों के लगभग ढाई लाख से अधिक शासकीय सेवकों को पदोन्नति दे दी गई है। पुलिस विभाग में ही 25 हजार अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद केवल सागर और उज्जैन में ही विश्वविद्यालय थे, लेकिन धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। वर्तमान समय में 75 से अधिक विश्वविद्यालय हो चुके हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी बनें, जहां विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता के साथ शिक्षा मिले। भविष्य में जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी एम्स की तर्ज पर विकसित की जाएगी। मेडिकल सेक्टर के सुदृढ़ीकरण के लिए यूनिवर्सिटी को सर्वसुविधायुक्त बनाने का यह मॉडल पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

अब तो चीता भी मध्यप्रदेश में जीता है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश टाइगर स्टेट तो पहले से ही है, अब तो कभी विलुप्त हो चुका चीता भी मध्यप्रदेश में जीता है। यह हमारा सौभाग्य है कि मध्यप्रदेश मगरमच्छ, घड़ियाल, गिद्ध, तेंदुआ जैसे वन्य जीवों के मामले में भी अग्रणी राज्य है। पूरे एशिया महाद्वीप से चीता विलुप्त हो चुका था, लेकिन मध्यप्रदेश की पावन धरती पर आते ही चीतों की संख्या 20 से बढ़कर 52 हो गई है। यह वन्य जीवों हमारे सहअस्तित्व की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। हम जियो और जीने दो की भावना के साथ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। असम से जंगली भैंसे लाए गए हैं। भविष्य में गैंडे और किंग कोबरा जैसे जीवों को भी लाकर उनके प्राकृतिक रहवास में बसाया जाएगा। वनों की समृद्धि के लिए और पर्यटन से रोजगार के अवसर दिलवाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम को लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने भी संबोधित कर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और लोक निर्माण विभाग के नवाचारों पर प्रकाश डाला। जबलपुर सांसद श्री आशीष दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में सरकार सबको साथ लेकर काम करती है। पिछले ढाई साल में विकास परियोजनाओं से जबलपुर का स्वरूप बदला है। राज्य सरकार अंत्योदय के भाव के साथ काम करते हुए हर वर्ग की चिंता कर रही है। क्षेत्रीय विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव नेतृत्व में मध्यप्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पास कर लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू करने के लिए विधेयक भी पारित कराया है। जबलपुर के महापौर श्री जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' ने कहा कि जबलपुर शहर को आज अमृत फेज-1 योजना के अंतर्गत हुए विकास कार्यों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में आगामी 7 अगस्त से प्रदेश भर में 'जन विश्वास अभियान' चलाया जायेगा। यह एक अनूठा अभियान है, जिसमें राज्य सरकार खुद नागरिकों के द्वार पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि जबलपुर नगर निगम ने शहर के प्रमुख नालों पर एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं, जिससे मां नर्मदा में मिलने वाले पानी को साफ किया जा रहा है। महापौर ने बताया कि जबलपुर देश का ऐसा शहर बन गया है, जहां कचरे से भी बिजली बनाई जा रही है। जबलपुर जिले में पौधरोपण अभियान के अंतर्गत 11 लाख पौधे रोपे जाएंगे।

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

सभी देशव

80 वें स्व

की



आप सबको आजादी के इस महान पर्व की अनेक-अनेक शुभकामनाएं। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र है- विकसित भारत। विकसित भारत बनाने के लिए ना हम रुकेंगे, ना हम झुकेंगे, और 2047 में विकसित भारत बना कर रहेंगे।

- नरेन्द्र मोदी

ासियों को
तंत्रता दिवस
हार्दिक शुभकामनाएँ



CBC 22201/13/0022/2627

राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर अंगदान जागरूकता के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार



सरोज वार्ता/ब्यूरो

अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अंगदान संकल्प अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा।भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे समारोह में राजस्थान को 'स्टेट अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस' से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने यह सम्मान राजस्थान की ओर से चिकित्सा शिक्षा विभाग की निदेशक डॉ. श्रीमती रश्मि गुप्ता, सोटो राजस्थान की संयुक्त निदेशक डॉ. चित्रा सिंह, आईईसी कंसल्टेंट डॉ. धर्मेश तथा अतिरिक्त निदेशक डॉ. ममता को प्रदान किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा– 'राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मिला यहसम्मान पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यह मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अंगदान के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने, प्रभावी जनसंपर्क अभियान चलाने तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को संवेदनशील और जनकेंद्रित बनाने के सतत प्रयासों का परिणाम है। अंगदान किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा मानवीय उपहार है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक अंगदान के महत्व को समझे और इस महाअभियान से जुड़े, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिल सके। ' प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा 'राजस्थान को प्राप्त यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदेश में अंगदान के क्षेत्र में विकसित हुई मजबूत संस्थागत व्यवस्था, प्रभावी समन्वय और जनभागीदारी का प्रमाण है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन , चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से अंगदान जागरूकता अभियान को व्यापक जनआंदोलन का स्वरूप मिला है। हमारा लक्ष्य प्रदेश में अंगदान के प्रति जागरूकता को और अधिक विस्तार देना तथा पारदर्शी एवं सुदृढ़ अंग प्रत्यारोपण व्यवस्था के माध्यम से अधिक से अधिक मरीजों को जीवनदान उपलब्ध कराना है।

● ' प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा 'राजस्थान को प्राप्त यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदेश में अंगदान के क्षेत्र में विकसित हुई मजबूत संस्थागत व्यवस्था, प्रभावी समन्वय और जनभागीदारी का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास ला रहे रंग

आयुष्मान आरोग्य मंदिर बदल रहे राजस्थान में जनस्वास्थ्य की तस्वीर



सरोज वार्ता/ब्यूरो

राजस्थान में गांव-ढाणी तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक बड़े बदलाव के रूप में उभरकर सामने आए हैं। पहले जहां सामान्य बीमारी के उपचार के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर दूर अस्पतालों का रुख करना पड़ता था, वहीं अब गांव और मोहल्ले के निकट ही बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर बच्चों के स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, मानसिक स्वास्थ्य, बुजुर्गों की देखभाल, टेलीमेडिसिन तथा आवश्यक जांच एवं दवाओं तक व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं घर के नजदीक ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 के अनुरूप देशभर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में गांव-ढाणी तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल रही है। राजस्थान में 18 हजार 436 स्वास्थ्य संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिनमें से अब तक करीब 11 हजार 500 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को पूरी तरह क्रियाशील किया जा चुका है, शेष संस्थानों को चरणबद्ध रूप से शुरू किया जा रहा है। राज्य में वर्तमान में 8,370 उप स्वास्थ्य केंद्र, 2 हजार 107 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 286 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 728 शहरी जनता क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित कर लोगों को नियमित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रशिक्षित कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ), एएनएम, स्टाफ नर्स और आशा कार्यकर्ता की टीम सातों दिन लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। इसका सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को मिल रहा है, जिन्हें अब छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिला अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में केवल सामान्य उपचार ही नहीं, बल्कि कॉम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के तहत 12 प्रकार की विस्तृत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें गर्भवती महिलाओं एवं प्रसव संबंधी सेवाएं, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों का उपचार, सामान्य ओपीडी सेवाएं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप सहित गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, आंख-कान-नाक एवं गला संबंधी सेवाएं, मुख स्वास्थ्य सेवाएं, जीरियाट्रिक एवं पेलिएटिव केयर, आपातकालीन प्राथमिक उपचार, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्क्रीनिंग एवं उपचार जैसी सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

●मरीज गांव में, विशेषज्ञ डॉक्टर अब स्क्रीन पर

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाओं को नया विस्तार मिला है। ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेजों से डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से मरीजों को अपने गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर ही विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श मिल रहा है। इससे अनावश्यक यात्रा, समय और खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है। अब तक राज्य में 31 लाख से अधिक लोग टेलीमेडिसिन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं।

●स्वास्थ्य जागरूकता भी बढ़ा रहे ये केंद्र

आयुष्मान आरोग्य मंदिर केवल उपचार तक सीमित नहीं हैं, होलिस्टिक एप्रोच के साथ लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। राज्यभर में अब तक इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 44.49 लाख से अधिक वेलनेस सत्रों का आयोजन किया जा चुका है।इन कार्यक्रमों से लगभग 4 करोड़ नागरिक लाभान्वित हुए हैं। इन वेलनेस सत्रों, स्वास्थ्य मेलों और विशेष स्वास्थ्य दिवसों के माध्यम से लोगों को योग, पोषण, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य तथा स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

●दवाइयां और जांच भी घर के पास

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर लोगों को 121 प्रकार की आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से दवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसी प्रकार इन केंद्रों पर 14 प्रकार की आवश्यक जांच सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन, गर्भावस्था जांच, ब्लड शुगर, मलेरिया, डेंगू, एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी, सिफिलिस, मूत्र जांच, पानी एवं नमक की गुणवत्ता जांच, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग सहित अन्य आवश्यक जांच शामिल हैं।

●जनस्वास्थ्य के नए मानकों की ओर बढ़ रहा प्रदेश

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को अस्पताल-केंद्रित व्यवस्था से निकालकर समुदाय आधारित व्यवस्था में बदला है। अब लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही है, आवश्यक दवाइयां और जांचें निःशुल्क मिल रही हैं तथा बीमारियों की समय रहते पहचान और उपचार संभव हो रहा है। राजस्थान में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का तेजी से विस्तार एक सुखद संकेत है कि स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र अब बड़े अस्पतालों से निकलकर आमजन के घरों के निकट पहुंच चुका है। गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का यह मॉडल राज्य में जनस्वास्थ्य के नए मानक स्थापित कर रहा है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाने में योगी सरकार ने हासिल की बड़ी उपलब्धि



सरोज वार्ता/ब्यूरो



उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक ओर उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाने के अभियान में प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष 100 जनपदों की सूची में अपने 17 जनपदों को शामिल कराया है। यह उपलब्धि न केवल प्रदेश में सौर ऊर्जा के तेजी से बढ़ते विस्तार को दर्शाती है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में उत्तर प्रदेश की मजबूत प्रगति का भी प्रमाण है। इस दौरान यूपी नेडा डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ में 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों के स्थापना के साथ-साथ देश का नंबर-1 जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। लखनऊ में बड़ी संख्या में घरों, द्वारा रूफटॉप सोलर अपनाए जाने से यह उपलब्धि संभव हुई है। वहीं, वाराणसी ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा को लेकर चल रहे अभियान का सकारात्मक असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर पहुंचकर प्रदेश के औद्योगिक शहरों में हरित ऊर्जा अपनाने की दिशा में नई मिसाल पेश कर रहा है। प्रदेश के 17 जनपदों का देश के शीर्ष 100 जिलों में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में रूफटॉप सोलर को लेकर जागरूकता, सरकारी प्रोत्साहन और योजनाओं का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, विशेषकर प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, के प्रभावी क्रियान्वयन से लाखों उपभोक्ता सौर ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। रूफटॉप सोलर संयंत्रों के विस्तार से लोगों को बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत हो रही है, साथ ही अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अवसर भी मिल रहा है। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिल रही है। उत्तर प्रदेश लगातार देश में रूफटॉप सोलर स्थापना की रफ्तार बढ़ा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा जनजागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। जिस गति से उत्तर प्रदेश में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो रहे हैं, उससे आने वाले समय में प्रदेश देश के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। देश के शीर्ष 100 जनपदों में 17 जिलों की मौजूदगी और लखनऊ का लगातार नंबर-1 स्थान, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उत्तर प्रदेश हरित ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व कर रहा है।

उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार, विनिर्माण और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026



सरोज वार्ता/ब्यूरो

उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार, विनिर्माण और निर्यात के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) का चौथा संस्करण आगामी 25 से 29 सितम्बर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार, उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ने पिछले तीन संस्करणों में प्रदेश के उत्पादों, उद्यमों और उद्योगों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बनाया है। अब यह आयोजन केवल एक व्यापार प्रदर्शनी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के विजन को आगे बढ़ाने वाला वैश्विक मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश यानी 'अनलिमिटेड पोटेंशियल' का प्रदेश है और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इस सामर्थ्य को अनुभव करने का सबसे प्रभावी मंच है। उन्होंने निर्देश दिए कि देश और विदेश में इस आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक निवेशक, खरीदार और आगंतुक इसमें सहभागी बनें। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष ट्रेड शो की थीम 'यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथः इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स' रखी गई है। आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.50 लाख से अधिक पंजीकृत बी2बी खरीदारों, 4.50 लाख से अधिक बी2सी आगंतुकों तथा 85 देशों से 550 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक एमओयू, ?3200 करोड़ से अधिक प्रस्तावित एमओयू मूल्य और ?13,500 करोड़ से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि इस बार ओडीओपी, ओडीओसी, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, रक्षा एवं एयरोस्पेस, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, पर्यटन एवं फिल्म, अक्षय ऊर्जा, ऑटो एवं इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मा एवं स्वास्थ्य, कौशल विकास, नागरिक उड्डयन, वित्तीय सेवाएं, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, खादी, वस्त्र, चमड़ा, फर्नीचर तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों का व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश की विविध औद्योगिक एवं आर्थिक क्षमता एक ही मंच पर प्रदर्शित होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नॉलेज सेशन को उद्योग जगत, निवेशकों और उद्यमियों के लिए उपयोगी बनाया जाए। इन सत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, बैंकिंग एवं वित्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नई श्रम संहिताएं, खाद्य प्रसंस्करण नीति, सड़क सुरक्षा, ई-कॉमर्स, वैश्विक मुक्त व्यापार समझौते, एमएसएमई तथा अन्य समकालीन विषयों पर विशेषज्ञ चर्चा आयोजित की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों के साथ उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी इस आयोजन की पहचान बने। इसके लिए सभी दिनों में शास्त्रीय संगीत, कथक, लोकनृत्य, लोकगायन, भजन, ग़ज़ल तथा अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आकर्षक आयोजन किया जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले अतिथि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का भी अनुभव कर सकें। बैठक में यह भी बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को जोड़ने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ व्यापक समन्वय किया गया है। विभिन्न देशों के खरीदारों से लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा है तथा बायर-सेलर बैठकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को नए वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ट्रेड शो के दौरान उद्यमी मित्रों की तैनाती सुनिश्चित करने तथा स्थानीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि आगंतुकों, खरीदारों और उद्यमियों को बेहतर सुविधा एवं सहयोग उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर ने कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग, वीआईपी आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था तथा आमजन की सुविधा के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। वहीं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने आयोजन स्थल पर विकसित की जा रही आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं की प्रगति से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान आगंतुकों की सुविधा के लिए ईवी बसों का संचालन भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो केवल व्यापारिक आयोजन नहीं, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित की जाएं, ताकि यह आयोजन उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, निवेश अनुकूल वातावरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रभावी परिचायक बनकर उभरे। मुख्यमंत्री ने बैठक में सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि प्रदेश को कौशल विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास का राष्ट्रीय केंद्र बनाने के उद्देश्य से तैयार की जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 27 मई को अभिरुचि आमंत्रण (ईओआई) जारी किया गया था, जिसमें बीवीजी समूह, टीसीएस और हीरानंदानी समूह ने रुचि दिखाई है। अधिकारियों की टीम टाटा आईआईएस केंद्रों का अध्ययन कर चुकी है, जबकि टीसीएस ने योजना के तकनीकी भागीदार के रूप में सहयोग देने पर सहमति व्यक्त की है। अब तक 19 जनपदों में लगभग 1320 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है तथा प्रथम चरण में एमएसएमई, यूपीसीडा, जीएनआईडीए, यीडा, यूपीईडा, बीडा और गीडा के माध्यम से 17 केंद्र विकसित किए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत नौ क्षेत्रीय हब एंड स्पोक मॉडल विकसित करते हुए प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण तथा 80 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं के प्लेसमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की



सरोज वार्ता/ब्यूरो

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सायं चंबा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चंबा जिला में सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि जिला में सड़कों के निर्माण और विस्तार पर 591 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। प्रदेश सरकार चंबा जिला के प्रत्येक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला के लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार ने चंबा में पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आधुनिक चिकित्सा अवसंरचना और नवीनतम स्वास्थ्य तकनीक उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया गया है। यहां पर लगभग 158 करोड़ रुपये की लागत से 200 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण किया गया है, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल विद्यार्थियों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को बेहतर कार्य एवं अध्ययन सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश सरकार आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए तथा जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर चंबा जिला की नंदनी को 'मिस मिंजर क्वीन' चुना गया। प्रसिद्ध पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल अंतिम सांस्कृतिक संध्या के मुख्य आकर्षण रहे। उन्होंने चंबा चौगान में उपस्थित दर्शकों का अपनी प्रस्तुति से भरपूर मनोरंजन किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, विधायक नीरज नैय्यर एवं हरदीप सिंह बावा, पूर्व मंत्री आशा कुमारी एवं ठाकुर सिंह भरमौरी, एपीएमसी चंबा के अध्यक्ष ललित ठाकुर, जिला कांग्रेस समिति चंबा के अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी, कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना एवं अमित भरमौरी, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी तथा अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।



वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए गेल ने 38,982 करोड़ का प्रचालन राजस्व तथा 4,292 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया

गेल (इंडिया) लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा की

सरोज वार्ता/ब्यूरो

इस तिमाही में गैस संचरण तथा द्रवीकृत हाइड्रोकार्बन खंड के प्रदर्शन में मजबूती दिखी। तथापि, भू-राजनीतिक परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों के कारण कंपनी ने गैस विपणन तथा पॉलिमर की मात्रा में कमी दर्ज की।

गेल ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 34,797 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में ?38,982 करोड़ का प्रचालन राजस्व दर्ज किया। पिछली तिमाही में 2,175 करोड़ की तुलना में ईबीआईटीडीए 6,948 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 5,773 करोड़ रहा, जबकि पिछली तिमाही में यह 1,577 करोड़ था। कर पश्चात लाभ (पीएटी) ?4,292 करोड़ रहा, जबकि पिछली तिमाही में यह 1,262 करोड़ था।

•वित्तीय प्रदर्शन (समेकित)

समेकित आधार पर, वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 35,705 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में प्रचालन राजस्व 41,350 करोड़ रहा। पिछली तिमाही में 2,703 करोड़ की तुलना में ईबीआईटीडीए 7,573 करोड़ रहा। पीबीटी ?6,268 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में यह 1,966 करोड़ था। पीएटी (अल्पमत हित के अलावा) 4,665 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में यह 1,485 करोड़ था।

पूंजीगत व्यय

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के दौरान, कंपनी ने अपनी दीर्घकालिक विकास रणनीति के अनुरूप लगभग 11,500 करोड़ के वार्षिक नियोजित पूंजीगत व्यय की तुलना में 6,176 करोड़ का पूंजीगत व्यय दर्ज किया।

प्रचालन संबंधी उपलब्धियां (वित्ती वर्ष 26-27 की पहली तिमाही बनाम वित्त0 वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही)

•प्राकृतिक गैस संचरण: 122.36 एमएमएससीएमडी बनाम 118.99 एमएमएससीएमडी

•गैस विपणन मात्रा: 93.82 एमएमएससीएमडी बनाम 101.88 एमएमएससीएमडी

•एलएचसी उत्पादन: 232 टीएमटी बनाम 194 टीएमटी

•पॉलिमर उत्पादन: 51 टीएमटी बनाम 153 टीएमटी





•एलपीजी संचरण: 1,077 टीएमटी बनाम 1,114 टीएमटी

प्राकृतिक गैस संचरण तथा एलएचसी उत्पादन में निरंतर वृद्धि गेल की मूलभूत अवसंरचना तथा द्रवीकृत हाइड्रोकार्बन प्रचालनों की मजबूती को दर्शाती है, जबकि गैस विपणन तथा पॉलिमर की कम मात्रा इस तिमाही के दौरान बाह्य व्यवधानों के प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है।

•अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

श्री दीपक गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गेल (इंडिया) लिमिटेड ने कहा: 'वित्त वर्ष 2026-27 का आरंभ पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न तीव्र अस्थिरता के बीच हुआ, जिसका प्रभाव गेल की कुछ मात्राओं पर पड़ा। कंपनी ने पोर्टफोलियो के लचीलेपन तथा स्पॉट सोर्सिंग के माध्यम से इस व्यवधान का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, साथ ही ग्राहकों की आवश्यकताओं तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन जारी रखा। गेल का विविधीकृत पोर्टफोलियो इस तिमाही का प्रभावी रूप से सामना करने में एक केंद्र बिंदु सिद्ध हुआ। संकट के दौरान ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के लिए मैं गेल टीम के निरंतर प्रयासों की सराहना करता हूँ। 'श्री गुप्ता ने यह भी सूचित किया कि गेल को पीएनजीआरबी से 3 एलपीजी पाइपलाइनों, अर्थात् झांसी-सितारगंज, चेरलापल्ली-नागपुर तथा शिक्रापुर-हुबली-गोवा के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। इन पाइपलाइनों की कुल लंबाई 1,800 किलोमीटर से अधिक है और तथा तीन वर्षों में इनमें लगभग 6,700 करोड़ का निवेश अनुमानित है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सूचित किया कि एनसीएलटी के आदेश के अनुपालन में कोंकण एलएनजी लिमिटेड (केएलएल), गेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

NTPC ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन की घोषणा की: स्टैंडअलोन PAT में 12% और ग्रुप PAT में 13% की बढ़ोतरी



सरोज वार्ता/ब्यूरो

भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी कंपनी, NTPC लिमिटेड ने 30 जून 2026 को खत्म हुई पहली तिमाही के लिए अपने बिना ऑडिट किए गए फाइनेंशियल नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी ने ऑपरेशनल फायदे और लगातार हो रही ग्रोथ के दम पर हर मोर्चे पर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। स्टैंडअलोन आधार पर, NTPC ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में ?44,512 करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (Q1 FY26) के मुकाबले 3% ज़्यादा है। Q1 FY27 में टैक्स के बाद मुनाफ़ा बढ़कर 5,342 करोड़ हो गया, जो Q1 FY26 में ?4,775 करोड़ था। PAT में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से कैपेसिटी बढ़ाने और ऑपरेशनल क्षमता में सुधार से हुई है। कंसोलिडेटेड आधार पर, NTPC ग्रुप का PAT Q1 FY27 में 13% बढ़कर 6,896 करोड़ हो गया, जो Q1 FY26 में 6,108 करोड़ था। ग्रुप कंपनियों के मुनाफ़े में 62% की बढ़ोतरी से इस शानदार परफॉर्मेंस को और मजबूती मिली; यह मुनाफ़ा Q1 FY26 के 1,131 करोड़ से बढ़कर Q1 FY26 में 1,832 करोड़ हो गया। NTPC के कोयले से चलने वाले पावर स्टेशन ऑपरेशनल क्षमता के मामले में इंडस्ट्री के लिए नए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। NTPC के कोयला प्लांट ने Q1 FY27 के दौरान 76.71% का प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया, जो भारत के बाकी कोयला प्लांट के 70.32% PLF से काफी बेहतर है। ये नतीजे लगातार ऑपरेशनल एक्सीलेंस और अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रोथ की रणनीति के दम पर भारत के पावर सेक्टर में NTPC की लीडरशिप की स्थिति को और मजबूत करते हैं।

IIFCL ने बॉन्ड/डिबेंचर के ज़रिए 1848 करोड़ सफलतापूर्वक जुटाए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए रिसोर्स बेस को मज़बूत किया



सरोज वार्ता/ब्यूरो

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय) के तहत पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, ने 4 साल, 11 महीने और 2 दिन की मैच्योरिटी वाले NCDs जारी करके सफलतापूर्वक 1848 करोड़ जुटाए हैं। इस इश्यू को निवेशकों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली; कुल 3048 करोड़ की बोलियां आईं, जो 500 करोड़ के बेस इश्यू साइज़ का लगभग 6 गुना है। आखिरकार, IIFCL ने 7.25% सालाना कूपन दर पर 1848 करोड़ की राशि रखने का फैसला किया। यह सफल इश्यू IIFCL की मज़बूत वित्तीय स्थिति, समझदारी भरे गवर्नेंस तौर-तरीकों और भारत सरकार की समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग संस्था के तौर पर इसकी रणनीतिक भूमिका में इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के गहरे भरोसे को दिखाता है। यह इश्यू FY 2026-27 के दौरान IIFCL की घरेलू बाज़ार से पहली उधारी है। यह चालू वित्त वर्ष के लिए कंपनी के संसाधन जुटाने के कार्यक्रम की शुरुआत का संकेत है और कैपिटल मार्केट से कुशलतापूर्वक संसाधन जुटाने की कंपनी की क्षमता को मज़बूत करता है। IIFCL घरेलू डेट कैपिटल मार्केट में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखेगी और फंडिंग की ज़रूरतों व मौजूदा बाज़ार की स्थितियों के आधार पर साल भर समय-समय पर बॉन्ड जारी करके बाज़ार से फंड जुटाती रहेगी। IIFCL के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बढ़ती फाइनेंसिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 34,200 करोड़ के एक बड़े रिसोर्स जुटाने के प्रोग्राम को मंज़ूरी दी है। इस प्रोग्राम में घरेलू बॉन्ड, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग जैसी अलग-अलग तरह की फंडिंग स्ट्रेटेजी शामिल है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ती लॉन्ग-टर्म फाइनेंसिंग उपलब्ध कराने के मकसद से अपनी फंड की लागत को कम से कम रखने की लगातार कोशिश करती रहती है। भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की पॉलिसी के अनुसार, IIFCL एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग के ज़रिए फंड जुटाने के मौकों पर भी विचार कर रहा है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा हाल ही में घोषित किए गए उपायों, जिनमें योग्य श्रेष्ठक के लिए रियायती USD-INR स्वैप सुविधा शामिल है, से हेजिंग की लागत कम होने की उम्मीद है। इससे विदेशी कर्ज़ लेना ज़्यादा आकर्षक बनेगा और प्रतिस्पर्धी दरों पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल हासिल करने का एक और ज़रिया मिलेगा। इस स्ट्रेटेजी के तहत, IIFCL अगले 2-3 महीनों में एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए लगभग 1.30 बिलियन स्ष्ठ जुटाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जाने की योजना बना रहा है। कंपनी भारत सरकार और अन्य रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से ज़रूरी मंज़ूरी मिलने पर विदेशी कर्ज़ के ज़रिए अतिरिक्त 1 बिलियन स्ष्ठ जुटाने का भी इरादा रखती है। सफलतापूर्वक फंड जुटाने पर IIFCL के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रोहित ऋषि ने कहा: 'इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पहले बॉन्ड इश्यू को मिले ज़बरदस्त रिस्पॉन्स से IIFCL की फाइनेंशियल मज़बूती, समझदारी से रिसोर्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के मकसद में इन्वेस्टर्स का भरोसा झलकता है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 34,200 करोड़ के मंज़ूरशुदा रिसोर्स जुटाने के प्रोग्राम के साथ, हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए लंबे समय तक और सही कीमत पर रिसोर्स की उपलब्धता पक्का करने के लिए घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट से अलग-अलग तरह से फंड जुटाने के तरीके को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 'इस इश्यू से मिली रकम और साल के दौरान जुटाए जाने वाले फंड, भारत सरकार के 'विकसित भारत 2047' के विज़न के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और सैनिटेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर एनर्जी और दूसरे अहम सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेंगे।

इंडियनऑयल ने 10 किलो और 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर की एक्सप्रेस डिलीवरी शुरू की



सरोज वार्ता/ब्यूरो

इंडियनऑयल के चेयरमैन श्री ए. एस. साहनी ने 'Indane XTRALITE NOW' लॉन्च किया। यह 10 किलो का एक नया कम्पोजिट LPG सिलेंडर है, जिसके साथ एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस भी मिलती है। इसे कंपनी के डायरेक्टर (मार्केटिंग) श्री सौमित्र पी. श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। आधुनिक घरों की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया 'Indane XTRALITE NOW', हल्के और जंग-रोधी कम्पोजिट सिलेंडर की टेक्नोलॉजी को डिजिटल सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ता है, ताकि ज़्यादा सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता मिल सके। इस सिलेंडर की बॉडी पारदर्शी है, जिससे LPG का लेवल आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही, इसमें बुकिंग के चार घंटे के अंदर एक्सप्रेस डिलीवरी, पसंदीदा समय पर डिलीवरी और बहुत कम कागज़ी कार्रवाई जैसी सुविधाएँ भी मिलती हैं। इस कार्यक्रम के दौरान, इंडियनऑयल के चेयरमैन ने लोकप्रिय 5 किलो वाले 'छोटू' सिलेंडर के लिए एक्सप्रेस होम डिलीवरी सर्विस भी शुरू की, जिसकी डिलीवरी अब बुकिंग के चार घंटे के भीतर की जाएगी। यह पहल शहरी घरों, प्रोफेशनल्स और छोटे परिवारों की ज़रूरतों के हिसाब से आसान और सुविधाजनक LPG समाधान देने के इंडियनऑयल के संकल्प को और मज़बूत करती है। इस मौके पर इंडियनऑयल के चेयरमैन श्री ए. एस. साहनी ने कहाः 'इनोवेशन तभी सार्थक होता है जब वह हमारे ग्राहकों के जीवन को बेहतर बनाए। Indane XTRALITE NOW एडवांस्ड कम्पोजिट सिलेंडर टेक्नोलॉजी को एक बेहतरीन सर्विस मॉडल के साथ जोड़ता है, ताकि LPG का अनुभव स्मार्ट, सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके। यह लॉन्च भविष्य के लिए तैयार एनर्जी सॉल्यूशन देने और कस्टमर सर्विस में नए मानक स्थापित करने के इंडियनऑयल के संकल्प को फिर से पक्का करता है। 'इंडियनऑयल के डायरेक्टर (मार्केटिंग) श्री सौमित्र पी. श्रीवास्तव ने कहाः 'आज के ग्राहक तेज़ी, सुविधा और एक आसान अनुभव की उम्मीद करते हैं। Indane XTRALITE NOW, नई टेक्नोलॉजी को तेज़ और भरोसेमंद डिलीवरी के साथ जोड़कर इंडियनऑयल के ग्राहक-केंद्रित नज़रिए को दिखाता है। यह घरेलू LPG अनुभव को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में एक और अहम कदम है। 'यह सुविधा शुरू में पुणे, गुरुग्राम, इंदौर और कोयंबटूर में उपलब्ध होगी। इसके बाद, अगस्त 2026 के मध्य तक इसे 25 और शहरों में और अक्टूबर 2026 के अंत तक देश भर के प्रमुख शहरों में शुरू किया जाएगा। ग्राहक इंडियनऑयल ह्हश्र ऐप और इंडियनऑयल कस्टमर वेबसाइट (httpsÑ//c&.indianoil.in) के ज़रिए नए कनेक्शन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और रिफिल बुक कर सकते हैं। जल्द ही WhatsApp (7588888824) के ज़रिए बुकिंग की सुविधा भी शुरू की जाएगी। यह नई सुविधा इंडियनऑयल के बड़े Indane डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और चुनिंदा इंडियनऑयल रिटेल आउटलेट्स के ज़रिए उपलब्ध होगी, जिससे यह आसानी से और बहुत सुविधा के साथ मिल सकेगी।

● यह घरेलू LPG अनुभव को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में एक और अहम कदम है। 'यह सुविधा शुरू में पुणे, गुरुग्राम, इंदौर और कोयंबटूर में उपलब्ध होगी। इसके बाद, अगस्त 2026 के मध्य तक इसे 25 और शहरों में और अक्टूबर 2026 के अंत तक देश भर के प्रमुख शहरों में शुरू किया जाएगा।

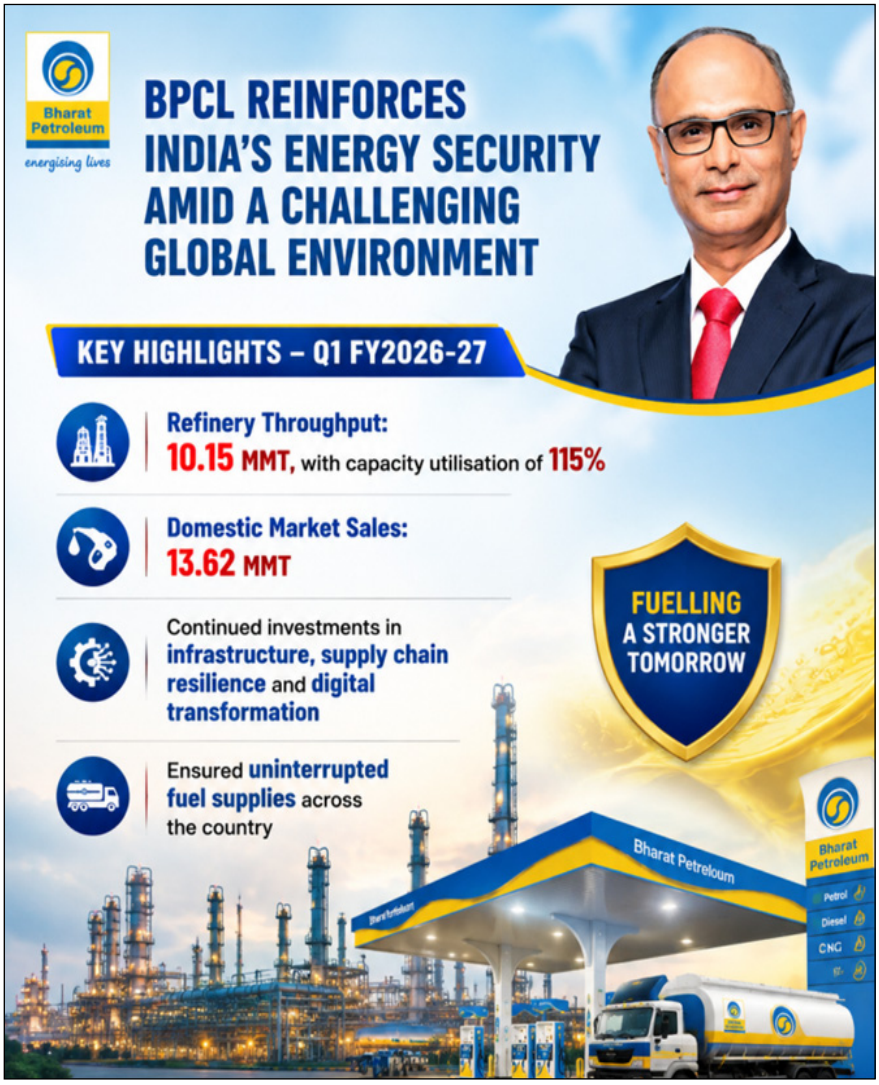
BPCL मुश्किल ग्लोबल माहौल के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मज़बूत कर रहा है

सरोज वार्ता/ब्यूरो

फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी और महारत्न PSU, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे घोषित किए। भू-राजनीतिक अनिश्चितता और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उतार-चढ़ाव के बावजूद, BPCL ने देश भर में बिना रुकावट एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। BPCL ने अपने रिफाइनिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सुचारू कामकाज बनाए रखकर राष्ट्रीय एनर्जी सुरक्षा को मजबूत किया। एक मजबूत सप्लाई चेन और अनुशासित कामकाज के ज़रिए, कंपनी ने शहरी, औद्योगिक और ग्रामीण बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों की बिना रुकावट उपलब्धता सुनिश्चित की। कंपनी ने रिफाइनिंग और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन कनेक्टिविटी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल क्षमताओं और उभरते हुए एनर्जी बिज़नेस में निवेश करना जारी रखा। BPCL ने भरोसेमंद और कुशल एनर्जी समाधान देने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिटेल ऑपरेशन्स और कस्टमर एंगेजमेंट में टेक्नोलॉजी-आधारित पहलों को भी तेज़ किया। इस तिमाही के दौरान, BPCL ने एडवांस्ड प्लानिंग सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स और रियल-टाइम सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करके पूरे देश में प्रोडक्ट प्लेसमेंट को बेहतर बनाया। इन उपायों से बदलते डिमांड, ऑपरेशनल निरंतरता और तेज़ी से बदलते ग्लोबल माहौल में भरोसेमंद प्रोडक्ट की उपलब्धता के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया देना संभव हुआ।

मुख्य बातें - Qv FY2026-27

- रिफाइनरी थ्रुपुटः 10.15 MMT, 115% क्षमता के इस्तेमाल के साथ
- घरेलू बाज़ार में बिक्रीः 13.62 MMT
- इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन की मज़बूती और डिजिटल बदलाव में लगातार निवेश
- देश भर में बिना रुकावट ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित की गई



भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में:

फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी, भारत पेट्रोलियम भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी और देश की प्रमुख इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनियों में से एक है। यह कंपनी कच्चे तेल की रिफाइनिंग और पेट्रोलियम उत्पादों की मार्केटिंग के साथ-साथ ऑयल और गैस इंडस्ट्री के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेक्टर में भी काम करती है। कंपनी को प्रतिष्ठित 'महारत्न' का दर्जा मिला है, जिससे यह ज़्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल आज़ादी वाली कंपनियों के ग्रुप में शामिल हो गई है। मुंबई, कोच्चि और बीना में स्थित भारत पेट्रोलियम की रिफाइनरियों की कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 35.3 MMTPA है। इसके मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इंस्टॉलेशन, डिपो, फ्यूल स्टेशन, एविएशन सर्विस स्टेशन और LPG डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क शामिल है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 25,300 से ज़्यादा फ्यूल स्टेशन, 1,000 से ज़्यादा CNG स्टेशन, 6,250 से ज़्यादा LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप, 440 से ज़्यादा ल्यूब्स डिस्ट्रीब्यूटरशिप, 81 POL स्टोरेज लोकेशन, 56 LPG बॉटलिंग प्लांट, 81 एविएशन सर्विस स्टेशन, 5 ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट और 6 क्रॉस-कंट्री पाइपलाइन शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में पावरग्रिड की दो परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और एक परियोजना की आधारशिला रखी



सरोज वार्ता/ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में POWERGRID के दो बड़े ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित किया और एक और अहम रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इससे एक मज़बूत ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के भारत के संकल्प को और मज़बूती मिली है। बिजली मंत्रालय के तहत आने वाली महारत्न PSU, 'पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड' द्वारा लागू किए गए इन प्रोजेक्ट्स का मकसद नेशनल ग्रिड को मज़बूत करना और कुरनूल व अनंतपुरम में पैदा होने वाली रिन्यूएबल एनर्जी को आसानी से आगे पहुँचाना है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स में कुल मिलाकर लगभग 9,920 करोड़ का निवेश शामिल है। प्रधानमंत्री ने कुरनूल विंड एनर्जी ज़ोन/सोलर एनर्जी ज़ोन (पार्ट-ए और पार्ट-बी) के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को देश को समर्पित किया, जिसे लगभग 3,547 करोड़ की लागत से विकसित किया गया था। इसके साथ ही, उन्होंने अनंतपुरम (2,500 MW) और कुरनूल (1,000 MW) में सोलर एनर्जी ज़ोन के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन किया, जिसे लगभग ?823 करोड़ के निवेश से बनाया गया

> ● ये निवेश भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और बेहतर ट्रांसमिशन क्षमता के ज़रिए कम-कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को तेज़ करने के प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। इन प्रोजेक्ट्स के भारत के 2030 तक 500 GW नॉन-फ़ॉसिल फ़्यूल-आधारित बिजली क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है।

था। ये अहम ट्रांसमिशन नेटवर्क आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी ज़ोन से रिन्यूएबल बिजली को कुशलतापूर्वक आगे पहुँचाने में मदद करेंगे और नेशनल ग्रिड के ज़रिए देश भर के उपभोक्ताओं तक इसकी भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करेंगे, जिससे भारत की तेज़ी से बढ़ती क्लीन एनर्जी क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुरनूल-IV रिन्यूएबल एनर्जी ज़ोन (REZ) - फ़ेज़-I (4.5 GW) के इंटीग्रेशन के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की आधारशिला रखी, जिसे 5,550 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट ग्रिड में अतिरिक्त 4.5 GW रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़कर अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क को काफ़ी मज़बूत करेगा। ये निवेश भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और बेहतर ट्रांसमिशन क्षमता के ज़रिए कम-कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को तेज़ करने के प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। इन प्रोजेक्ट्स के भारत के 2030 तक 500 GW नॉन-फ़ॉसिल फ़्यूल-आधारित बिजली क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। 30 जून, 2026 तक, POWERGRID 291 सबस्टेशन, 1,86,595 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन और 6,34,516 MVA ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्षमता का संचालन करता है, साथ ही एडवांस्ड ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए 99.80% से ज़्यादा की शानदार ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता बनाए रखता है। ये नए प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन और टिकाऊ आर्थिक विकास में सहयोग देने में POWERGRID की लीडरशिप को और मज़बूत करते हैं।

कोल इंडिया का क्यू1 मुनाफ़ा बढ़कर 8,852 करोड़ हुआ, 5.50 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया



सरोज वार्ता/ब्यूरो

कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफ़िट में मामूली बढ़ोतरी की जानकारी दी। ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव के बावजूद, ऑपरेशन से ज़्यादा रेवेन्यू मिलने से यह बढ़ोतरी संभव हो पाई। कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, 30 जून, 2026 को खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफ़िट सालाना आधार पर 0.6% बढ़कर 8,852 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 8,797 करोड़ था। अपने वित्तीय नतीजों के साथ-साथ, सरकारी कोयला खनन कंपनी ने 5.50 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया, जिससे स्थिर वित्तीय प्रदर्शन के बीच शेयरधारकों को फायदा हुआ। अप्रैल-जून तिमाही में ऑपरेशन से होने वाली कमाई 7.8% बढ़कर 46,255 करोड़ हो गई, जो क्यू1 एफवाई26 में 42,919 करोड़ थी। यह बढ़ोतरी कोयले की बेहतर बिक्री और बिजली व इंडस्ट्री जैसे अहम सेक्टर से लगातार बनी मांग को दिखाती है। हालांकि, कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दबाव में रहा। ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन से पहले की कमाई सालाना आधार पर 4.1% घटकर 12,069 करोड़ (पहले 12,588 करोड़) रह गई, जबकि EBITDA मार्जिन पिछले साल की तिमाही के 29.3% से घटकर 26.1% हो गया, जो ज़्यादा ऑपरेटिंग लागत और मार्जिन पर दबाव को दर्शाता है। बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने एफवाई27 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 5.50 का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है। कंपनी ने योग्य शेयरधारकों की पहचान के लिए 31 जुलाई, 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया है और डिविडेंड का भुगतान 25 अगस्त, 2026 को या उससे पहले किया जाएगा। कोल इंडिया भारत की सबसे बड़ी डिविडेंड देने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनियों में से एक बनी हुई है; मज़बूत कैश जेनरेशन और घरेलू कोयला खनन सेक्टर में अपनी मज़बूत स्थिति के कारण यह नियमित रूप से डिविडेंड देती रही है।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत सरकार को डिविडेंड का चेक सौंपा



सरोज वार्ता/ब्यूरो

भारतीय जीवन बीमा निगम के सीईओ और एम डी, श्री आर. दोराईस्वामी ने केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को 12,207.25 करोड़ का डिविडेंड चेक सौंपा। यह राशि भारत सरकार के हिस्से का डिविडेंड है, जिसे 27 जुलाई, 2026 को हुई सालाना आम बैठक में शेयरधारकों ने मंजूरी दी थी। इस मौके पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री संजय लोहिया के साथ-साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के एम डी श्री रत्नाकर पटनायक, एम डी श्री आर. चंदर और नॉर्दर्न ज़ोन के ZM (I/C) श्री एन.एस. राघवा भी मौजूद थे। भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी स्थापना के 70 शानदार साल पूरे कर रही है और 31.03.2026 तक इसका एसेट बेस 59.03 लाख करोड़ है। यह भारतीय जीवन बीमा बाज़ार में मार्केट लीडर बनी हुई है।

पुलिस कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करे सरकार



सरोज वार्ता/ब्यूरो

इसमें दो राय नहीं कि किसी आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के किन्हीं परिस्थितियों में उग्र होने और जन-धन की हानि रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन को कार्रवाई करनी होती है। इसमें भी दो राय नहीं है कि राज्य के पास हिंसा को रोकने और कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का भी है कि लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे विरोध को रोकने के लिए प्रयोग की गई ताकत का स्तर क्या रहा। जाहिर है राष्ट्रविरोधी ताकतों, हिंसक भीड़ तथा छात्रों के आंदोलन को एक ही तौर-तरीके से नहीं निपटा जा सकता है। इसी आलोक में सवाल पैदा होता है कि जंतर-मंतर से शुरू हुए संसद चलो मार्च को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई ताकत क्या जरूरी थी? क्या उचित तरीके से अधिकृत थी? ऐसा ही विवाद इस आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर खड़ा हुआ है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने शुरुआत से ही पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया। जबकि बाद में जनरल डायरी में यह दर्ज किया गया कि रैपिड एक्शन फोर्स ने एंटी-रायट गन से दो राउंड फायरिंग की थी। वहीं दूसरी ओर छात्र प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। खासकर, कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष ने गृह मंत्री पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर तीखे प्रहार किए हैं। वे बाकायदा गृह मंत्री के इस्तीफे को लेकर लगातार अभियान चलाते रहे हैं। इसी बीच सूचना के अधिकार के तहत दिल्ली के दो अस्पतालों से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार बीस जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम दस लोगों को पैलेट गन से चोट लगी थी। इन अस्पतालों में पैलेट गन से आहत छात्रों ने उपचार कराया था। निस्संदेह, पैलेट गन से घायल होने वालों का यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है, न कि किसी बिना पुष्टि वाले दावों पर आधारित है। दरअसल, पैलेट गन की जद में आये छात्रों के अनुभव परेशान करने वाले रहे हैं। खबरों के अनुसार, कुछ प्रदर्शनकारियों के चेहरों, छाती और आंखों पर चोट आई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि एक छात्र की आंख की रोशनी भी जा सकती है। सार्वजनिक विमर्श में सवाल उठाये जाते रहे हैं कि छात्र आंदोलनकारियों के विरुद्ध पैलेट गन का इस्तेमाल करने का तार्किक आधार क्या है। वहीं दूसरी ओर कानून-व्यवस्था बनाये रखने के दौरान मेटल पैलेट गन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा था कि मौजूदा नियमों के तहत विशेष परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे हथियार रखने की कानूनी वैधता और किसी खास घटना में इनके गलत इस्तेमाल के आरोपों के बीच फर्क किया है। निस्संदेह, इस फर्क की सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए। इसके इस्तेमाल के बाद किसी तरह का विवाद न हो, इसलिए स्थिति को साफ करने के लिए पारदर्शिता अपनाना भी बेहद जरूरी है। इससे जुड़े कई तथ्यों को लेकर सावधानी बरती जानी चाहिए, जिसमें गोला-बारूद का पर्याप्त रिकॉर्ड रखना, सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस की बातचीत का रिकॉर्ड और साथ ही मेडिकल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। साथ ही इन तथ्यों की स्वतंत्र जांच की जानी भी जरूरी है। वहीं दूसरी ओर सरकार का भी दायित्व बनता है कि भीड़ को काबू करने में पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े तमाम नियम स्पष्ट रूप से बताए जाएं। वहीं दूसरी ओर यदि इनका अंधाधुंध प्रयोग किया गया हो तो इसके लिये जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना भी बेहद जरूरी है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत में विरोध करने का अधिकार एक घोषित संवैधानिक स्वतंत्रता है। इसकी रक्षा के लिए संयम की जरूरत अपरिहार्य शर्त है। यह दोनों तरफ से जरूरी है- प्रदर्शनकारियों और सरकार की तरफ से। लेकिन विडंबना है कि अक्सर देश में पुलिस व सुरक्षाबल छात्रों के धरनों व प्रदर्शनों के दौरान बात-बात पर निर्ममता से लाठी भांजते नजर आते हैं।

● निस्संदेह, इस फर्क की सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए। इसके इस्तेमाल के बाद किसी तरह का विवाद न हो, इसलिए स्थिति को साफ करने के लिए पारदर्शिता अपनाना भी बेहद जरूरी है। इससे जुड़े कई तथ्यों को लेकर सावधानी बरती जानी चाहिए, जिसमें गोला-बारूद का पर्याप्त रिकॉर्ड रखना, सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस की बातचीत का रिकॉर्ड और साथ ही मेडिकल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाना जरूरी है।

संसदीय समिति की रिपोर्ट से उठते सवाल-

प्राइवेट अस्पतालों और स्कूलों की लूट पर कब लगेगी लगाम?

संतोष कुमार पाठक

पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में प्राइवेट यानी निजी अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों की बाढ़ सी आ गई है। देश के राज्य और जिले तो छोड़िए , अब तो छोटे-छोटे शहरों में भी खुलते जा रहे नर्सिंग होम और स्कूल लोगों की जेब काटने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। देश का गरीब तबका तो छोड़िए, मध्यम आय और उच्च मध्यम आय की कैटेगरी में आने वाले लोग भी इनकी लूट से परेशान होते जा रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों को लेकर आई संसदीय समिति की एक रिपोर्ट ने फिर से इस घाव को ताजा कर दिया है। एक बार फिर से वही पुराना सवाल उठ कर खड़ा हो गया है कि खुली लूट का अड्डा बन चुके प्राइवेट अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों की मनमानी पर आखिर कब लगाम लगेगी? देश के प्राइवेट अस्पताल, भर्ती होने वाले मरीजों/ उनके परिजनों से कमरे का जो किराया वसूलते है, यह उसी इलाके के महंगे होटलों से भी कई गुना ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, इलाज के नाम पर जो बाकी चार्ज लिए जाते हैं वो कमरे के चार्ज में अलग से जोड़ा जाता है। यह सारे खुलासे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट से हुए हैं। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों में इलाज का खर्च औसतन 6,631 रुपए है जबकि प्राइवेट अस्पतालों में यही खर्च साढ़े सात गुने से भी ज्यादा (50,508 रुपए) है। इलाज के नाम पर भी अनाप-शनाप वसूली की जाती है। बिल में पारदर्शिता नहीं होती है, गंभीर इलाज या सर्जरी से पहले मरीज को फाइनल खर्च का एस्टिमेट नहीं बताया जाता है। नतीजा प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी बेलगाम होती जा रही है और जिसकी जो मर्जी वो वसूल रहा है। मुंबई के नानावटी अस्पताल में कमरे का चार्ज 6 से 12 हजार रुपए प्रतिदिन है जबकि उसी इलाके के 3 स्टार होटल में कमरे कमरे का चार्ज 2500 से लेकर 4500 रुपए के बीच ही है। दिल्ली के साकेत में स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती मरीज से अस्पताल वाले 7-11 हजार रुपए प्रतिदिन कमरे का चार्ज वसूलते है जबकि अस्पताल के पास ही स्थित होटल में आपको 2100 से 3500 रुपए प्रतिदिन के आधार पर बढ़िया कमरा मिल सकता है। यही हाल देश के ज्यादातर शहरों में प्राइवेट अस्पतालों का है। समिति ने सरकार को कुछ सुझाव देते हुए यह सिफारिश की है कि, प्राइवेट अस्पताल के कमरे का किराया 3 स्टार होटल के किराए से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्ती से पहले अस्पताल को इलाज का पूरा खर्च स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। सर्जरी और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए फिक्स रेट तय होना चाहिए और उसमें सभी खर्चे शामिल होने चाहिए। इसके अलावा भी संसदीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिश करते हुए सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए है। समिति ने स्पष्ट तौर पर सरकार को सरकारी अस्पतालों में बेड और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने को कहा है। हालांकि यह सब जानते हैं कि सरकार ऐसा करेगी नहीं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय समिति की रिपोर्ट की आड़ लेकर कहीं वैसा ही खेल न कर दें जैसा कि CGHS चार्ज के मामले में किया गया है। सरकार को यह याद दिलाना बेहद जरूरी है कि दिल्ली या मुंबई के महंगे अस्पतालों में इलाज का खर्च इन शहरों के हिसाब से है वहीं देश के दूर-दराज इलाकों में इलाज का खर्च उस इलाके के आधार पर है। डर इस बात का है कि कहीं CGHS में जो गलतियां की गई है,उसी तरह की गलती को इस मामले में



दोहराते हुए दिल्ली या मुंबई के आधार पर इलाज़ और सर्जरी का फिक्स रेट पूरे देश के लिए न तय कर दिया जाए। ऐसे हालात में दूर-दराज के इलाकों में चलने वाले प्राइवेट अस्पताल सरकारी आदेश का हवाला देते हुए कई गुना पैसा वसूलना शुरू कर देंगे। सरकार , सरकार के मंत्री और अधिकारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। जब भी प्राइवेट अस्पतालों की खुली लूट का जिक्र आता है तो आप इससे स्कूलों और कॉलेजों को अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से एक छोटे नर्सिंग होम को बड़ा और भव्य अस्पताल बनने में देर नहीं लगती, उसी तरह से स्कूल और कॉलेजों की बिल्डिंग भी साल दर साल भव्य से भव्यतम होती चली जाती है। फीस, किताबें, ड्रेस और बाकी खर्चों की मनमानी के बारे में तो सबको मालूम है। इसलिए यहां पर हम सिर्फ कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहेंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्थित एक मेडिकल कॉलेज से MBBS करने की कुल लागत सवा से डेढ़ करोड़ रुपए के बीच आती है। मिडिल क्लास तो छोड़िए , हाई इनकम ग्रुप में आने वाले लोगों के लिए भी अब अपने बच्चों को MBBS करवा पाना आसान नहीं रहा है। आजकल प्राइवेट स्कूलों में लूट का एक जरिया स्मार्ट बोर्ड यानी स्मार्ट क्लासेस भी बन चुका है। एक बार स्मार्ट बोर्ड लगा दिया और फिर उसके बाद सालों तक इसके नाम पर स्कूल वाले वसूली करते हैं। अलग-अलग इलाकों के आधार पर स्मार्ट क्लास के नाम पर प्राइवेट स्कूल वाले 200 रुपए से लेकर 800 रुपए महीने तक वसूलते हैं। पहली कक्षा से बारहवी तक, हर महीने.. हर साल..। हालत इतनी खराब है कि अगर इन स्कूलों में जाकर आप अध्यापकों से स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाने को कहेंगे तो ज्यादातर शिक्षकों को शायद यह चलाना भी नहीं आएगा लेकिन हर महीने वसूली जारी है। संसदीय समिति भले ही कितने भी गंभीर सवाल उठाए या कितने ही अच्छे सुझाव दें लेकिन कड़वी सच्चाई तो यही है कि प्राइवेट अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों की मनमानी एवं खुली लूट पर लगाम कसने का कोई स्थायी फॉर्मूला सरकारों के पास नहीं है और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता जिम्मेदार हैं क्योंकि पिछले तीन दशकों में देश के तमाम राजनीतिक दल कहीं न कहीं किसी न किसी सरकार में भागीदार/साझीदार रहे हैं इसलिए कोई भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता है।

अमन की राह में रोड़ाः शांति योजना को ठुकराने का इजराइल का फैसला



सरोज वार्ता/ब्यूरो

गाजा पर इजराइल की बमबारी और तबाही को कथित तौर पर खत्म करने वाले अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष-विराम को लगभग एक साल हो गया है। लेकिन इस युद्धविराम के बाद से, इजराइल के हमलों में तकरीबन 1,300 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और उसकी सेना का इस पट्टी के लगभग 65 फीसदी हिस्से पर कब्जा है, जहां 20 लाख की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मलबे के बीच तंबू वाले शिविरों में रह रहा है और स्कूल-अस्पताल बंद पड़े हैं। मदद पर जहां अभी भी बहुत ज्यादा रोक लगी हुई है, वहीं इजराइल ने पुनर्निर्माण का काम रोक रखा है और उसकी जिद है कि हमास पहले अपने हथियार छोड़े। फिर भी, जब हमास ने धीरे-धीरे इजराइली सेना की वापसी के साथ-साथ - डोनाल्ड ट्रम्प के की अगुवाई वाले 'बोर्ड ऑफ पीस' के प्रस्तावित 15-सूत्री खाके के तहत - अमेरिकी समर्थन वाले फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के साथ मिलकर अपने भारी हथियारों को हटाने और उन्हें स्टोर करने पर सहमति जताई, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल '15-सूत्री दस्तावेज' को खारिज कर रहा है और जब तक हमास 'भारी हथियार, हल्के हथियार यानी सारे हथियार' नहीं छोड़ देता, तब तक कोई वापसी नहीं होगी। इजराइल सिर्फ हमास के निरस्त्रीकरण ही नहीं, बल्कि गाजा को पूरी तरह अपने अधीन करने के लिए भी उत्सुक है। भले ही आम नागरिकों और बच्चों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही हो। जहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल पर नरसंहार की कार्यवाही चल रही है, वहीं अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। साथ ही, अदालतों में उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा भी चल रहा है। हमास को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने का वादा करके, नेतन्याहू कट्टर राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी गुट का समर्थन बनाए रखकर सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे पीछे हटने या कोई रियायत देने पर सहमत होते हैं, तो अक्टूबर में होने वाले चुनावों में उनके दक्षिणपंथी गठबंधन को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रम्प और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान में सत्ता बदलने के मकसद से जो युद्ध शुरू किया था, वह एक बड़ी नाकामी साबित हुआ है। इससे ईंधन का संकट पैदा हो गया है, जिसका असर कई देशों पर पड़ा है। होर्मुज जलडमरूमध्य में ठीक से आवाजाही न हो पाने के चलते अमेरिका में पेट्रोल और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। इसी वजह से ट्रम्प पश्चिम एशिया में कोई ऐसी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं जिससे उनकी साख बनी रहे। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नजदीक आने के साथ ही इजराइल के प्रति सहानुभूति कम हो रही है और यही तथ्य बोर्ड के प्रस्ताव की वजह भी बताता है। भले ही उस बेतुके बोर्ड की 'नए गाजा' की परिकल्पना - जिसमें मुक्त व्यापार क्षेत्र (फ्री-ट्रेड ज़ोन) और निजी बुनियादी ढांचे का प्रावधान तो है, लेकिन बोर्ड में फिलिस्तीनियों की कोई भागीदारी नहीं है - विनाशकारी संघर्ष के बाद खुलेआम मुनाफा कमाने की कोशिश जैसी लगती हो, लेकिन इस 15-सूत्री प्रस्ताव का गाजा के बुरी तरह प्रभावित लोगों द्वारा असल में स्वागत ही किया जाएगा। हमास के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं, इसलिए हथियार छोड़ना उसके लिए जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही इजराइल को भी पीछे हटना होगा। ट्रम्प और उनके सलाहकारों को यह सोचना चाहिए कि क्या वाशिंगटन द्वारा दशकों पुराने उस समझौते - जिसमें इजराइल की शर्तों पर उसे हथियार दिए जाते रहे और उसका बचाव किया जाता रहा - को जारी रखना सही है या फिर क्या वह इजराइल को असल में पीछे हटने के लिए मजबूर करने के वास्ते उसके मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता होने के नाते अपने दबदबे का इस्तेमाल करेगा। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है।

पंजाब के लोग इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को देंगे करारा जवाबः नायब सिंह सैनी

सरोज वार्ता/ब्यूरो



हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्षों तक न्याय और सम्मान की प्रतीक्षा कर रहे डीएससी समाज को जहां हरियाणा में वर्तमान सरकार ने शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया वहीं पंजाब में डीएससी समाज के आरक्षण का कोटा खत्म किया जा रहा है। नौकरी में सिलेक्शन और मेडिकल टेस्ट होने के बावजूद पंजाब सरकार ने डीएससी समाज के युवाओं को ज्वाइनिंग के समय घर भेजने का काम किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कारगुजारियों को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोग इन दोनों पार्टियों को करारा जवाब देंगे। पंजाब में भाजपा सरकार बनने के बाद डीएससी समुदाय को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के फरीदकोट में आयोजित विमुक्त जाति समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार की नीतियों की आंकड़ों सहित तुलना करते हुए पंजाब सरकार को घेरा और आमजन से आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनवाने का आह्वान किया ताकि पंजाब के लोगों के साथ कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुई अनदेखी को दूर किया जा सके और पंजाब को भी हरियाणा जैसी नीतियों का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में वर्तमान सरकार बनते ही हमने डीएससी समाज के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को कोटा दिया और इसके बाद 5600 पुलिस कर्मियों की भर्ती में डीएससी समाज के 604 बच्चों को बिना सिफारिश तथा बिना पैसे नौकरियां दीं। इसी प्रकार हरियाणा में अभी हाल ही में ग्रुप-डी के 3200 बच्चे भर्ती किए गए जिनमें से डीएससी समाज के 334 गरीब बच्चों को नौकरियां मिली हैं। दूसरी ओर पंजाब में भर्ती के बाद भी वंचित समुदाय के बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पिछले दिनों एक्साइज इंस्पेक्टर की भर्ती के दौरान अपने आप को आम आदमी तथा ईमानदार सरकार कहने वालों का सच पंजाब ही नहीं बल्कि देश की जनता के सामने खुल गया है। इस भर्ती में हुई धांधली ने मान सरकार की ईमानदारी का चौला सबके सामने उतर गया है। इस भर्ती में अपना नाम के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डीआईपीएस और 'इक दिन करमां वाला' आदि लिखने वाले बच्चों का चयन किया गया है। इस परिणाम पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्टे लगा दिया गया है। पंजाब में इस प्रकार से नौकरियां बिक रही हैं जो पंजाब के युवाओं के साथ सरासर धोखा है। श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अक्सर पंजाब के लोग उनके पास चंडीगढ़ आकर कहते हैं कि जो सुधार भाजपा सरकार ने हरियाणा में लागू किए हैं उन्हें पंजाब में भी लागू किया जाए, इसके लिए पंजाब की जनता आगामी चुनावों में भाजपा को वोट देने को तैयार है। पंजाब में सरकार और मुख्यमंत्री केवल चुटकुले और बातें करके मन बहला रहे हैं लेकिन वास्तव में सरकार का काम चुटकुले सुनाना नहीं बल्कि जनता के हित में काम करना होता है जिसमें पंजाब सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने हरियाणा में सरकार बनाने से पहले 217 घोषणाएं की थीं जिनमें से 70 घोषणाएं डेढ़ साल के कार्यकाल में पूरी की हैं। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से पूछा कि पंजाब की जनता जानना चाहती है कि उन्होंने चुनाव पूर्व किए 57 में से कितने वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को बताया कि हमने हरियाणा में माताओं-बहनों को 2100 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था जिसके लिए सरकार के पहले ही बजट में 5000 करोड़ रुपये का तथा दूसरे बजट में 6500 करोड़ रुपये का प्रावधान करके अपना वादा निभाया। सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल में बहनों के खातों में 1650 करोड़ रुपये भिजवाए जा चुके हैं। जबकि पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया गया था लेकिन आज पांच साल बाद दोबारा चुनाव होने के केवल चार महीने बचे हैं और अभी भी पंजाब की बहनों-माताओं को यह लाभ नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों के इलाज के लिए आयुष्मान योजना लागू की, हरियाणा ने आयुष्मान योजना के साथ चिरायु योजना के साथ इसका दायरा बढ़ाया और 1.5 करोड़ लोगों को योजना में शामिल किया। पिछले कुछ समय में हरियाणा के 40 लाख लोगों का 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवाया गया है जिस पर सरकार ने 4000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अब गरीब परिवारों को इलाज के लिए जमीन या गहने नहीं बेचने पड़ते हैं, इलाज के खर्च की चिंता परिवार नहीं, सरकार करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर हरियाणा में 70 साल से अधिक के सभी बुजुर्गों का इलाज भी सरकार के खर्च पर हो रहा है जिस पर 8 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डीएससी व डीएनटी समाज के लाखों लोगों को भाजपा सरकार ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में अपना मकान तथा प्लाट देने का काम किया है। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा पिछले 12 सालों में गरीब परिवारों को 1.60 लाख मकानों की चाबियां सौंपी गई हैं। इस सरकार द्वारा डीएससी समाज के गरीब परिवारों को मकान देने के लिए 3 कार्यक्रम सोनीपत, जींद व गुरुग्राम में किए जा चुके हैं, चौथा कार्यक्रम जल्द ही फरीदाबाद में किया जाएगा जिसमें 4000 परिवारों को फ्लैट की चाबियां सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों की पेंशन 1500 से 2500 करने का वादा किया था जिसे वह आज तक पूरा नहीं कर सकी है। इसके विपरीत हरियाणा में बुजुर्गों को सम्मान स्वरूप 3200 रुपये दिए जा रहे हैं। हरियाणा में गरीब परिवारों की रसोई में हरियाणा सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर पहुंचा रही है। इसके अलावा किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस किया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पंजाब में सरकार बनने के बाद इन योजनाओं को यहां भी लागू करने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वंचित समाज को समान अवसर, सामाजिक सम्मान और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समाज के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को केवल स्वीकार करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे दूर करने के लिए ठोस नीतियों और संवेदनशील शासन की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से स्टील अथॉरिटी ऑफ़इंडिया लिमिटेड के सीएमडी डॉ. अशोक कुमार पांडा ने की मुलाकात



सरोज वार्ता/ब्यूरो

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से कांकेरोडरांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी डॉ0अशोक कुमार पांडा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी।इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, निदेशक-प्रभारी बोकारो स्टील प्लांट श्री प्रियरंजन एवं अधिशासी निदेशक सेल (खनन) श्री वी0मानवटी उपस्थितर हे।

झारखंड में आधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण को नई दिशा: जमशेदपुर में बनेगा IDTR, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी पहल

झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren ने झारखंड मंत्रालय में परिवहन विभाग और Tata Motors Limited के बीच इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जमशेदपुर की स्थापना के लिए हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुरक्षित, कुशल और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण ड्राइविंग प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि IDTR की स्थापना से युवाओं को आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी और राज्य में सड़क सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास, रोजगार सृजन और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। टाटा मोटर्स के सहयोग से स्थापित होने वाला यह संस्थान प्रशिक्षित एवं दक्ष चालकों के निर्माण के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा।

● ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया होगी सरल और पारदर्शी



कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पलामू, सरायकेला-खरसावां, धनबाद सहित विभिन्न जिलों के लाभार्थियों से सीधे संवाद कर ड्राइविंग एवं लर्निंग लाइसेंस प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आवेदक को अनावश्यक परेशानी न हो तथा विशेष रूप से हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को अधिक सरल, सुगम और पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही सभी जिलों के उपायुक्तों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

● महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण, लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को अधिक सुलभ एवं पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि वे कौशल विकास के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

● परिवहन व्यवस्था को मिलेगा नया आयाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स के बीच यह साझेदारी राज्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और दक्ष बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने बताया कि IDTR में आधुनिक तकनीक और वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण के साथ सड़क सुरक्षा, दुर्घटना नियंत्रण तथा परिवहन क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा।

● 10 हजार से अधिक नागरिकों को मिला लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज राज्य के 10 हजार से अधिक नागरिकों को ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया जितनी सरल और पारदर्शी होगी, उतना ही आम नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि प्रत्येक पात्र आवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए।

भागवत की नजरों में जेन-जी आंदोलन का दृष्टिकोण



ललित गर्ग

जंतर-मंतर से उठी हाल की युवा आवाजों ने भारतीय लोकतंत्र के सामने कई नए प्रश्न खड़े किए हैं। आंदोलन को लेकर समाज में दो मत हो सकते हैं, आंदोलन की शैली, नेतृत्व और उसके राजनीतिक इस्तेमाल पर भी बहस हो सकती है, लेकिन एक बुनियादी सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने, असहमति व्यक्त करने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का युवाओं और विशेषकर जेन-जी को लेकर दिया गया दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। उन्होंने साफ कहा कि नई पीढ़ी सवाल करती है, तर्कसंगत उत्तर चाहती है, उसे केवल आदेश देकर नहीं समझाया जा सकता। उनके अनुसार आज जरूरत 'डिक्टेशन' की नहीं, 'डिस्कशन' की और आदेश की नहीं, सहमति की है। भागवत ने हाल में इससे भी आगे बढ़कर कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संवाद का एक वैध माध्यम है और जेन-जी के आंदोलन में उठाई गई शिकायतें जायज हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विरोध करने वालों को राष्ट्रविरोधी कह देना उचित नहीं है। उनका मानना है कि आंदोलन का उद्देश्य समाज में विभाजन पैदा करना नहीं, बल्कि सहमति और समाधान की दिशा में आगे बढ़ना होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत और छात्रों की नाराजगी के बीच संबंध की ओर भी उन्होंने संकेत किया। भागवत के इस दृष्टिकोण की सराहना इसलिए भी की जानी चाहिए कि यह केवल किसी एक आंदोलन या किसी एक सरकार का प्रश्न नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की उस मूल आत्मा को स्पर्श करता है, जिसमें सत्ता जनता से शक्ति प्राप्त करती है और जनता की आवाज सुनना उसकी संवैधानिक तथा नैतिक जिम्मेदारी है। विरोध को हमेशा विद्रोह मान लेना लोकतंत्र की समझ को संकुचित करना है। असहमति को राष्ट्रविरोध समझना उससे भी बड़ी भूल है। राष्ट्र सरकार से बड़ा है और लोकतंत्र सत्ता से बड़ा। जो नागरिक देश के भविष्य को लेकर सवाल करता है, वह जरूरी नहीं कि देश का विरोध कर रहा हो, कई बार वह देश को बेहतर बनाने की बेचैनी व्यक्त कर रहा होता है। आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर जब हम स्वतंत्र भारत की उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं, तब हमें यह भी पूछना चाहिए कि हमारी आजादी का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या आजादी केवल तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान गाने और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने तक सीमित है? या इसका अर्थ यह भी है कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर सवाल कर सके, व्यवस्था की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सके और अपनी बात बिना भय के रख सके? यदि हम सचमुच विकसित भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत का सपना देखते हैं तो हमें भारत के युवाओं के सपनों को सुनना ही होगा। भारत के महान चिंतकों ने युवाशक्ति को राष्ट्रनिर्माण का आधार माना है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को जागने, अपनी शक्ति पहचानने और लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया था। उनके चिंतन का मूल संदेश यही था कि युवा केवल राष्ट्र का भविष्य नहीं,

● भारत के महान चिंतकों ने युवाशक्ति को राष्ट्रनिर्माण का आधार माना है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को जागने, अपनी शक्ति पहचानने और लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया था। उनके चिंतन का मूल संदेश यही था कि युवा केवल राष्ट्र का भविष्य नहीं, वर्तमान की सक्रिय शक्ति भी हैं।

वर्तमान की सक्रिय शक्ति भी हैं। महात्मा गांधी का विश्वास था कि परिवर्तन केवल सत्ता के गलियारों से नहीं आता, वह जागरूक नागरिकों की चेतना से आता है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने बार-बार युवाओं के सपनों को भारत के भविष्य से जोड़ा। उनके लिए सपना वह नहीं था जो सोते समय दिखाई देता है, बल्कि वह था जो व्यक्ति को सोने नहीं देता। आज के युवाओं की बेचैनी को इसी दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी और पिछली पीढ़ी के बीच अंतर स्वाभाविक है। पहले परिवार, विद्यालय और समाज में 'क्यों' पूछने की गुंजाइश कम थी, बड़े जो कहते थे, उसे मान लेना संस्कार समझा जाता था। आज का युवा प्रश्न करता है-क्यों, कैसे और किसलिए? वह केवल परंपरा के नाम पर किसी बात को स्वीकार नहीं करता। वह प्रमाण चाहता है, तर्क चाहता है और परिणाम देखना चाहता है। यह बदलाव चुनौती भी है और अवसर भी। यदि हम इस प्रश्नाकुलता को दबाएंगे तो कुंठा पैदा होगी, यदि इसे सही दिशा देंगे तो यही प्रश्न नवाचार, अनुसंधान और राष्ट्रनिर्माण की शक्ति बनेंगे। विचारों के टकराव से घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय संस्कृति स्वयं 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः' की संवाद परंपरा से विकसित हुई है। उपनिषदों में प्रश्न हैं, उत्तर हैं, पुनः प्रश्न हैं। भगवान महावीर की अनेकांत दृष्टि हमें सिखाती है कि सत्य को एकांगी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। एक ही विषय के अनेक पक्ष हो सकते हैं। इसलिए बहस लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी बौद्धिक ताकत है। समस्या बहस में नहीं, बहस के हिंसक हो जाने में है, समस्या असहमति में नहीं, असहमति के नाम पर अराजकता में है। इसीलिए भागवत की बात का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है-विरोध संविधान की मर्यादा में हो, शांतिपूर्ण हो और उसका लक्ष्य व्यक्ति को अपमानित करना नहीं, व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाना हो। आंदोलन लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक अनुशासन के साथ। सरकार की आलोचना लोकतंत्र है, हिंसा लोकतंत्र नहीं। प्रश्न करना स्वतंत्रता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वतंत्रता नहीं। इसलिए सरकार और आंदोलनकारी-दोनों की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी अधिक बड़ी है, क्योंकि उसके पास सत्ता, प्रशासन और संस्थागत शक्ति होती है। किसी छात्र की आवाज को लाठी से दबाया जा सकता है, लेकिन उसकी आशंका को लाठी से समाप्त नहीं किया जा सकता। किसी आंदोलनकारी को राष्ट्रविरोधी कह देने से उसका प्रश्न समाप्त नहीं हो जाता। यदि उसकी मांग गलत है तो तथ्य और तर्क से उसे गलत सिद्ध किया जाए। यदि मांग सही है तो उसे स्वीकार करने में संकोच क्यों? लोकतंत्र में सरकार का सबसे प्रभावी हथियार पुलिस नहीं, संवाद है। यहां मोहन भागवत की भूमिका एक मार्गदर्शक की तरह दिखाई देती है। उन्होंने अनेक अवसरों पर केवल प्रशंसा करने के बजाय व्यापक सामाजिक हित के प्रश्न उठाए हैं। जब सत्ता या व्यवस्था किसी दिशा में आवश्यकता से अधिक आगे बढ़ती दिखाई देती है, तब एक जिम्मेदार मार्गदर्शक का दायित्व होता है कि वह उसे आत्ममंथन की ओर ले जाए। भागवत की यह भूमिका हमें महाभारत के भीष्म पितामह की याद दिलाती है-ऐसे व्यक्ति की, जो सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी समय-समय पर धर्म, मर्यादा और व्यापक हित की याद दिलाता है। यह तुलना व्यक्ति-पूजा के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका की व्याख्या के लिए है। सरकारें जब जनता की आवाज समय पर सुनती हैं तो आंदोलन समस्या बनने से पहले समाधान बन सकता है। लेकिन जब शिकायतें महीनों और वर्षों तक फाइलों में पड़ी रहती हैं, जब संवाद के रास्ते बंद होते जाते हैं और जब नागरिक को लगता है कि उसकी सुनवाई नहीं होगी, तब असंतोष सड़क पर आता है। फिर वही आंदोलन राजनीतिक दलों, अवसरवादी तत्वों और निहित स्वार्थों के लिए मैदान बन जाता है। परिणामतः मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और आंदोलन का चरित्र बदलने लगता है। यही वह स्थिति है जिससे लोकतंत्र को बचाना है। नीट और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने भी यही संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार और संस्थाओं को असाधारण संवेदनशीलता दिखानी होगी। परीक्षा केवल एक प्रश्नपत्र नहीं होती, वह लाखों परिवारों के वर्षों के परिश्रम, सपनों और आर्थिक-सामाजिक आकांक्षाओं से जुड़ी होती है। यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसकी मेहनत निष्पक्ष व्यवस्था में नहीं आंकी गई, तो उसका आक्रोश स्वाभाविक है। हाल के छात्र आंदोलनों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। इस संदर्भ में पुलिस की भूमिका भी पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। हर प्रदर्शनकारी अपराधी नहीं होता और हर नारा राष्ट्रविरोधी नहीं होता। पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। राष्ट्रविरोधी गतिविधि और जायज नागरिक असहमति के बीच अंतर करना लोकतांत्रिक पुलिस व्यवस्था की पहली कसौटी है। इसलिए मोहन भागवत की बात को केवल जेन-जी आंदोलन के संदर्भ में देखने की बजाय उसे भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के व्यापक संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकारें आएंगी-जाएंगी, राजनीतिक दल बदलेंगे, आंदोलनों के स्वरूप बदलेंगे, लेकिन लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता नहीं बदलेगी, जनता को सुनना होगा।



अफसरों को जिम्मेदार ठहराने से होगा समस्याओं का समाधान



योगेन्द्र योगी

देश की सरकारों के पास हर समस्या का एक लाइलाज रामबाण इलाज यह है कि किसी समस्या की गहराई के उपचार के बजाए कानून बना दिया जाए। सरकारें हर समस्या का इलाज व्यवहारिक धरातल पर नहीं बल्कि कानून में ढूंढने की आदी हो चुकी हैं। देश में हर क्षेत्र में एक के बाद एक नए कानून बनाए जा रहे हैं, किन्तु समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जितने भी नए कानून बनाए जा रहे हैं, या पुराने कानूनों मे संशोधन किया जा रहा, उसका सारा भार देश के आम लोगों पर ही डाला जा रहा है। इन कानूनों में कहीं लापरवाही बरतने या अनदेखी के लिए देश के आला अफसर जिम्मेदार नहीं हैं। आजादी से लेकर आज तक ऐसा कोई कानून केंद्र या किसी राज्य ने नहीं बनाया है कि यदि कोई घटना–दुर्घटना या कांड होगा तो उसके लिए सीधे अफसर भी जिम्मेदार माने जाएंगे। संशोधित केंद्रीय पेपर लीक कानून में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा होगी। अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया

> ● भारत के महान चिंतकों ने युवाशक्ति को राष्ट्रनिर्माण का आधार माना है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को जागने, अपनी शक्ति पहचानने और लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया था। उनके चिंतन का मूल संदेश यही था कि युवा केवल राष्ट्र का भविष्य नहीं, वर्तमान की सक्रिय शक्ति भी हैं।

गया है। संगठित अपराधों में 7 से 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक का नया केंद्रीय कानून बनाने के बावजूद झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताएं हुईं। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जेपीएससी के चेयरमैन एल. खियांगटे ने इस्तीफा भी दे दिया। केंद्र सरकार के बनाए पेपर लीक परीक्षा कानून देश में एक अगस्त से अस्तित्व मे आ चुका है। इसके बावजूद देश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले थम नहीं रहे हैं। राजस्थान में अप्रैल 2022 में एंटी पेपर लीक एक्ट लागू किया गया। गुजरात में मार्च 2023 से सख्त नकल और पेपर लीक विरोधी कानून लागू। उत्तराखंड में वर्ष 2023 में प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश/कानून लागू किया गया। झारखंड में वर्ष 2023 में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया। हरियाणा में सितंबर 2021 से प्रभावी कानून लागू है। इसी तरह असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी अलग-अलग वर्षों में इससे जुड़े कड़े कानूनी प्रावधान या अधिनियम बनाए जा चुके हैं। केंद्र और इतने राज्यों में पेपर लीक कानून के बाद भी पेपर लीक की घटनाएं थम नहीं रही है। पेपर लीक की तरह देश में बलात्कार के मामलों में बेहद कठोर कानून बनाए गए थे। बलात्कार और इसके साथ हत्या के मामलों में फांसी तक का प्रावधान किया गया है। 2012 में दिल्ली में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषी चार भारतीय पुरुषों को फांसी दे दी गई थी। निर्भया बलात्कार हत्याकांड से लोगों में आक्रोश फैल गया था और

भारत में बलात्कार विरोधी नए कानून बनाए गए। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के बलात्कार में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। गैंग रेप में न्यूनतम सजा 20 साल से आजीवन की गई। इतने कठोर कानून के लागू होने के बावजूद देश में बलात्कार–हत्या के मामले बढ़ते चले गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल 2023 में 31,982 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुए। इससे जाहिर है कि नए कठोर कानूनों का अपराधियों को कोई भय नहीं है। ये कानून महज कागज का पुलिन्दा साबित हो रहे हैं। यही भ्रष्टाचार का भी हाल है। देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कठोर कानून बने हुए हैं, इसके बावजूद देश से भ्रष्टाचार खत्म होना तो दूर बल्कि कम तक नहीं हो सका। आए दिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती हैं। भ्रष्टाचार खत्म नहीं करने के लिए कभी किसी अफसर को जिम्मेदार नहीं माना गया। बेशक उनके विभाग का ही कोई भ्रष्टाचारी क्यों न पकड़ा जाए। आज तक जितने भी कानून बनाए गए हैं, उसमें अफसरों की जिम्मेदारी कहीं भी तय नहीं की गई। मसलन सड़क पर गडढा होने से यदि कोई सड़क दुर्घटना होती है या फिर बगैर अग्नि सुरक्षा उपायों के संचालित किसी व्यवसायिक भवन में अग्नि दुर्घटना होती है तो इसके निगरानी करने वाले अफसर जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, ऐसा कोई कानून नहीं बना है। यही प्रमुख वजह है कि चाहे पेपर लीक हों या किसी तरह का बड़ा हादसा, कानूनों को सख्त कर दिया

● राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल 2023 में 31,982 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुए। इससे जाहिर है कि नए कठोर कानूनों का अपराधियों को कोई भय नहीं है। ये कानून महज कागज का पुलिन्दा साबित हो रहे हैं। यही भ्रष्टाचार का भी हाल है। देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कठोर कानून बने हुए हैं, इसके बावजूद देश से भ्रष्टाचार खत्म होना तो दूर बल्कि कम तक नहीं हो सका। आए दिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती हैं।

जाता है, किन्तु जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। इसका बड़ा उदाहरण मेलों, धार्मिक स्थलों पर होने वाले आयोजनों में भगदड़ के दौरान होने वाली मौतें हैं। ऐसा शायद ही कोई साल जाता होगा, जब ऐसे हादसे नहीं होते होंगे। ऐसे हादसों में अब तक देश भर में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद अफसरों की ज्मिमेदारी तय नहीं की गई। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया कि ऐसे आयोजनों में हादसों के लिए सीधे अफसर जिम्मेदार ठहराएं जाएंगे, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा और उन्हे जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। अफसरों की लापरवाही से हुए हादसों और इससे बच निकलने का बड़ा उदाहरण राजस्थान का है। जहां दो साल पहले स्कूल की छत गिरने से 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, इसके बाद भी स्कूल की छत गिरने या दीवार गिरने के हादसे होते रहे, किन्तु एक भी अफसर को आपराधिक आरोपी नहीं माना गया। किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस ने आईएएस अफसर तो दूर बल्कि शिक्षा विभाग के किसी अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। राजस्थान सहित देश के लाखों सरकारी स्कूलों की इमारतों की हालत खस्ता है। सरकारों के पास इतना बजट ही नहीं है कि इतना रखरखाव किया जा सके। यह निश्चित है कि चुनी हुई सरकारें लंबे अर्से तक देश के लोगों की आंखों में धूल नहीं झौंक सकती, उन्हें कानून बनाने के साथ ही धरातल पर समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। देश में बुनियादी सुविधाओं की पहुंच आम नागरिकों तक बढ़ानी होगी। इसकी कमी से हर साल बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के अभाव जैसे मुद्दों पर धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होते हैं, किन्तु इनका स्थायी समाधान नहीं होता। सरकारों की हालत 'खेत खाए गदहा और मार खाए जुलहा' जैसी है। जब तक सरकारें और जिम्मेदार अफसर अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे। ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बेशक कितने भी नए कानून बन जाएं।



असामाजिक हो रहे सोशल मीडिया का नियमन जरूरी

उमेश चतुर्वेदी



दिल्ली में बीस जुलाई को काकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के जेन जी के संबोधन की वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत चर्चा में हैं। चर्चा से ज्यादा उनकी भूमिका कहीं ज्यादा विमर्श के केंद्र में है। इसमें दो राय नहीं कि दुनियाभर में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रचलन में हैं, उनमें से ज्यादातर विदेशी हैं। जाहिर है कि वे उन जगहों के कानूनों और सांस्कृतिक परंपराओं से ज्यादा संचालित हैं, जहां उनके मुख्यालय हैं। इसलिए अपने व्यापक हितों के लिए वे अपने प्रचलन वाले देशों की परंपराओं और संस्कृतियों को सवालों के घेरे में लाने, उसका उपहास उड़ाने और उन्हें तार-तार करने वाला अलगोरिदम उन्होंने विकसित कर रखा है। जिसका खामियाजा तीसरी दुनिया के देश और वहां की सांस्कृतिक परंपराएं उठा रही हैं। सोशल मीडिया को लोकतंत्र के बड़े मंच के रूप में 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिशिया के सिटी बौजिज शहर में फलों का ठेला लगाने वाले मोहम्मद बोआजीजी की आत्महत्या के बाद हुए उबाल के बाद देखा जाने लगा। म्यूनिसिपल कर्मचारियों की सख्ती के चलते क्षुब्ध बोआजीजी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। किसी ने इस घटना को सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया के तत्कालीन अलगोरिदम ने इस घटना को इस रूप में प्रस्तुत किया कि समूचे अरब जगत में उबाल आ गया। नागरिक अधिकारों की स्थापना और लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर अरब देशों की जनता सड़कों पर उतर आई। इसका ही नतीजा मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर चौक पर दिखा। जहां महीनों तक लोग जमे रहे और वहां के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। यह आग सीरिया, यमन और लीबिया तक जा पहुंची। वहां के पारंपरिक शासकों के खिलाफ लोगों का दबा हुआ गुस्सा निकला और कई जगह सत्ताएं बदल गईं। भारत में भी इसके ही कुछ महीनों बाद अन्ना हजारे को आगे रखकर एक आंदोलन छेड़ा गया। जिसकी परिणति आम आदमी पार्टी के रूप में हुई और वह दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। फिर पंजाब में भी उसने पैठ बना ली। इन घटनाओं को याद करना इसलिए जरूरी है कि इन सबके पीछे सोशल मीडिया के जरिए त्वरित गति से फैलाई गई सूचनाओं का हाथ सबसे ज्यादा रहा। तब सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया गया। सोशल मीडिया के बारे में कहा गया कि लोकतंत्र में सबकी आवाज पहुंचाने और उन्हें मौका देने का यह बड़ा माध्यम है। इसे लोकतंत्र के वाजिब और जरूरी औजार के रूप में भी मान्यता मिली। लेकिन बीतते वक्त के साथ पता चल रहा है कि जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, वह लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा अनसोशल यानी असामाजिक भी है। यह ठीक है कि सोशल मीडिया के जरिए व्यवस्था की अंधी सुरंग में खो रही आवाजों को मौका मिलता है। लेकिन यह उतना ही सच है कि इस माध्यम ने लोगों की नजर का पानी उतार दिया है। लोग अब लिहाज करना भूल गए हैं। सोशल मीडिया पर अगर किसी की बात पसंद नहीं आती तो उसे खुलेआम गालियां दी जा सकती हैं। उसके चरित्र पर आक्षेप लगाया जा सकता है। उसका चरित्र हनन किया जा सकता है। चाहे वह व्यक्ति सामाजिक जीवन में कितना ही प्रतिष्ठित क्यों न हो, उसकी उम्र चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सोशल मीडिया मंचों ने अपना अलगोरिदम भी ऐसा विकसित किया है, जो अच्छी बातों, सामाजिक चिंतन और बेहतर कल की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देखा। एक तरह से कहें तो वह इसकी अनदेखी ही करता है। लेकिन जैसे ही किसी को कोई गाली देता है, किसी के चरित्र का बेवजह ही हनन करता है, किसी का घटिया कार्टून बनाता है, सोशल मीडिया का अलगोरिदम उसे फैलाने में द्रुत गति से जुट जाता है। सोशल मीडिया ने अब तक पर्दे के पीछे रही नंगई को भी उजागर कर दिया है। आज रील्स के चक्कर में अधनंगे और कई बार करीब-करीब नग्न फोटोग्राफ और वीडियो तक जारी किए जा रहे हैं। भले ही अपने परिवारों में महिलाएँ और युवतियां सलीके से रहती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने और उसके जरिए कुछ कमाने के चक्कर में अपने शील और अपनी लज्जा को भी बेपर्दा कर रही हैं। सोशल मीडिया कितना असमाजिक हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसका अलगोरिदम अश्लीलता को बढ़ावा देता है, लेकिन शील और लज्जा की बात को अपने मंच के किसी कोने में डाल देता है। कह सकते हैं कि वर्चुअल स्पेस के किसी अंधेरे कोने में उसे गुम कर देता है। तीन साल पहले प्यू रिसर्च सेंटर ने 19 विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में सोशल मीडिया को लेकर एक शोध किया था। उसके मुताबिक, आम नागरिकों की नजर में सोशल मीडिया राजनीतिक जीवन के लिए रचनात्मक और विनाशकारी दोनों है। इस अध्ययन में शामिल देशों में, औसतन 57 प्रतिशत लोगों ने माना कि सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लेकिन इसे बिनाशकारी मानने वालों की संख्या भी कम नहीं रही। करीब 35 प्रतिशत से ज्यादा लोगों का का कहना था कि सोशल मीडिया विनाशकारी साबित हो रहा है।

आप सभी का धन्यवाद

सरोज वार्ता के बढ़ते कदम

सरोज के सफल 12 वर्ष का सफ़र



सरोज वार्ता

आप सभी सुधी पाठक, विज्ञापनदाताओं का हार्दिक आभार प्रकट करता है जिन्होने सरोज वार्ता का हर कदम पर साथ दिया

Coming Soon

Kavya Fashion Products





www.kavyafashionproducts.com





